



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

No. 115]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2003/वैशाख 16, 1925
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2003/VAISAKHA 16, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

अन्तिम निष्कर्ष

विषय :— इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड से शुद्ध टैरिफथैलिक एसिड (पीटीए) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा सम्बन्धी पाटनरोधी जांच।

संख्या 14/9/2002-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. क्रियाविधि

1. निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के उपर्युक्त नियमों के तहत प्राधिकारी के दिनांक 4 सितम्बर, 1997 के मूल प्रारंभिक निष्कर्षों तथा

दिनांक 21 नवंबर, 1997 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 85/97, दिनांक 19 मार्च, 1998 के अन्तिम निष्कर्ष सं० 14/1/1996-डीजीएडी तथा दिनांक 28 अप्रैल, 1998 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 13/98 में यथानिर्दिष्ट पीटीए (शुद्ध टैरिफथैलिक एसिड) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए रखे रहने की आवश्यकता संबंधी पुनरीक्षा की निर्णायक समीक्षा की जो थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा जाएगा) से निर्यातित या इनके मूल का है। सियम मित्सुई पीटीए कं० लि० और पीटी ऐमोको मित्सुई पीटीए इंडोनेशिया के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के संबंध भी पोतवणिक समीक्षा क्रमशः दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 तथा दिनांक 12 नवंबर, 1998 को अधिसूचना सं० 7/2/98-डीजीएडी द्वारा की गई थी और अन्तिम परिणाम दिनांक 16 जून, 1999 को अधिसूचित किए गए। इसकी मध्यावधि पुनरीक्षा के निष्कर्ष दिनांक 29.5.2000 की अधिसूचना सं० 26/1/98-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उसमें कोरिया गणराज्य से पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

- (ii) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 मई, 2002 की सार्वजनिक सूचना में अधिसूचित किया जो वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के तहत अध्याय-29 में वर्गीकृत शुद्ध टैरिफथैलिक एसिड के आयातों के बारे में थी जो संबद्ध देशों से निर्यातित अथवा उनके मूल का है।
- (iii) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे पहले की गई जांच के अनुसार उपलब्ध हैं) और उद्योग/प्रयोक्ता संगठनों को भेजी और उसमें नियम 6(2) के अनुसार उन्हें अपने-अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने देने का अवसर दिया।
- (iv) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध उत्पाद के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे पहले की गई जांच के अनुसार उपलब्ध हैं) उक्त सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति भेजी और उन्हें यह सलाह दी कि वे नियम 6(2) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर दें।
- (v) नियम 6(2) के अनुसार जांच आरंभ किए जाने की सूचना नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावासों को दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के सभी संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेज दें। ज्ञात निर्यातक को भेजे गए

पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावास को भी भेजी गई। मैसर्स पीटी पोली प्राइमा कयरिस्का, इण्डोनेशिया से उत्तर प्राप्त हुआ था।

- (vi) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से अनुरोध किया गया कि वे जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में संबद्ध माल के किए गए आयातों के ब्यौरे दें।
- (vii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचना की एक प्रति प्रदान की।
- (viii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने हेतु ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी।
- (ix) नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक जानकारी हेतु संबद्ध माल के आयातकों/प्रयोक्ता संगठनों, जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, को प्रश्नावली भेजी गई। इस प्रश्नावली का उत्तर/जानकारी आयातक मैसर्स इण्डो-रामा सिंथेटिक्स लि०, नई दिल्ली ने दी।
- (x) मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि० (आरआईएल), मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, मुंबई से क्षति संबंधी जानकारी ली गई। मैसर्स आर आई एल द्वारा उत्पादन की कुल लागत/क्षति जानकारी प्रस्तुत की गई। मैसर्स बाम्बे डाइंग ने उत्पाद डीएमटी के संबंध में कुछ लागत-निर्धारण-जानकारी प्रस्तुत की।
- (xi) संबद्ध माल के भारत में उत्पादन की इष्टतम लागत, निर्माण एवं बिक्री लागत की गणना करने हेतु मैसर्स आरआईएल, मुंबई की भी लागत जांच की गई जो सामान्यतया स्वीकृत सिद्धान्तों (जीएएपी) और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित थी।
- (xii) सभी इच्छुक पक्षकारों को अपने-अपने विचार दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 को मौखिकतौर पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दर्ज कर दें। पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां एकत्र करें और उनका खण्डन, यदि कोई हो, व्यक्त करें।
- (xiii) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपान्तर प्राधिकारी द्वारा बनाई गई सार्वजनिक फाइल पर उपलब्ध कराया और उसे इच्छुक पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा।

(xiv) उपर्युक्त नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए आवश्यक तथ्यों/आधार का इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 9 अप्रैल, 2003 को खुलासा किया गया।

(xv) इस अधिसूचना में x x x का आशय यह है कि किसी इच्छुक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी गोपनीय आधार पर तथा यह प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत ठीक समझी गई है।

(xvi) जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसंबर, 2001 तक रही।

ख. घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ता संगठनों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार और प्राधिकारी द्वारा जांच

2. विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचार प्रकटन विवरण-पत्र में दिए गए हैं। ऐसे जिन विचारों पर पहले प्रकटन विवरण-पत्र में चर्चा नहीं हुई है और जिन्हें अब प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में उठाया गया है, जहां तक वे नियमानुसार संगत हैं और वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, उन पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच, जहां कहीं उचित समझा गया, नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

निर्णायक समीक्षा की पहल

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 19.3.1998 की अन्तिम निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/1/96 और तत्पश्चात् दिनांक 29.5.2000 की समीक्षा अधिसूचना सं0 26/2/98-डीजीएडी के अनुसरण में इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुद्ध टैरिफथैलिक एसिड(जिसे इसके बाद पीटीए कहा जाएगा) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ की। यह निर्णायक समीक्षा दिनांक 22.5.2002 की अधिसूचना सं0 14/9/2002-डीजीएडी द्वारा आरंभ की गई।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद शुद्ध टैरिफथैलिक एसिड (जो पीटीए के नाम से लोकप्रिय है और जिसे इस जांच में इसके बाद पीटीए कहा गया है)

5. पीटीए का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2917.36 और इसके अलावा, आईटीसी 29173600 के तहत किया गया है। पीटीए एक सफेद अघुलनशील पाउडर और किसी दृश्य सम्मिश्रण से मुक्त है और इसका प्रयोग पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ), पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाई), पोलिएस्टर टैरीथिएलेट (पीईटी), बोतल ग्रेड रेजिन और पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न फिल्म में होता है।

6. पीटीए का स्थानापन्न उत्पादन डाइ-मिथाइल टेरेपथेलेट (डीएमटी) है। इस उत्पाद के बारे में कोई तर्क विचाराधीन नहीं है। इन उत्प्रेरकों का विस्तृत तकनीकी विवरण मूल जांच और संबद्ध सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में प्रस्तुत है। चूंकि मौजूदा जांच वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के तहत केवल एक समीक्षा है, अतः प्राधिकारी का यह निर्णय है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा यथाउपरोक्त मूल जांच तक ही सीमित है।

7. समान वस्तु की परिभाषा संबंधी नियम 2(घ) में यह दिया गया है कि समान वस्तु का अर्थ एक ऐसी वस्तु से है जो प्रत्येक दृष्टि से जांच के अधीन वस्तुओं जैसी या उसके समान हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में किसी ऐसी वस्तु से है जिसके गुण जांच के अधीन वाली वस्तु से काफी मिलते-जुलते हैं। समान वस्तु के उपर्युक्त परिभाषा के प्रथम भाग से यह स्पष्ट है कि समान वस्तु जांच के अधीन वस्तु से सभी प्रकार से समरूप या सदृश होनी चाहिए। समान वस्तु शब्द के क्षेत्र में वे वस्तुएं निश्चित रूप से शामिल होंगी जो कि हर तरह से समरूप या सदृश वस्तुओं के अभाव में जांच के अधीन वस्तुओं से काफी मिलते जुलते गुणवाली हैं। इस प्रकार कानून के अंतर्गत समान वस्तु शब्द की व्याख्या के लिए 'की अनुपस्थिति में' शब्द का उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह निविवाद है कि अनुपस्थिति में' शब्द को घरेलू उद्योग के केवल इस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि क्या समान वस्तु का उत्पादन करने वाला 'घरेलू उद्योग' है या नहीं। दूसरे शब्दों में अगर समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाला कोई घरेलू उद्योग नहीं है तब कानून प्राधिकारियों को इस शब्द के क्षेत्र में उन वस्तुओं को भी शामिल करने की अनुमति देता है जिनके गुण काफी मिलते हैं। प्राधिकारी को स्मरण है कि मुख्य जांच के दौरान डीएमटी को पाटनरोधी जांच के संदर्भ में समान वस्तु के रूप में माना गया था क्योंकि तब ऐसा कोई घरेलू उद्योग नहीं था जो पीटीए के मिलती-जुलती वस्तु का उत्पादन कर रहा था। मौजूदा निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि मैसर्स आर आई एल नाम घरेलू उद्योग है जो पीटीए से मिलते-जुलते वस्तु का उत्पादन कर रहा है। इसलिए, प्राधिकारी समझते हैं कि घरेलू

उद्योग द्वारा उत्पादित पीटीए को इस जांच में शामिल संबद्ध देशों से आयातित पीटीए के समान वस्तु माना जाए ।

पहल, समीक्षा, स्थिति और घरेलू उद्योग

आयातक मैसर्स इन्डो-रामा सिंथेटिक्स (इं.) लि० (आईआरएसएल), नई दिल्ली के विचार

8. इन्डो रामा सिंथेटिक्स (इं.) लि०, (आईआरएसएल) यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पीटीए निर्णायक समीक्षा का यह मामला एक असाधारण मामला है । मैसर्स बॉम्बे डाइंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडीएमएल) द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मूल मामला आरंभ किया गया जिसमें पीटीए के पाटन का आरोप लगाया गया लेकिन तथाकथित समान उत्पाद डीएमटी पर क्षति होने का दावा किया गया । मूल जांच में पाटन मूल्यों का निर्धारण उत्पाद पीटीए के आधार पर किया गया जबकि क्षति विश्लेषण पूर्णतया डीएमटी (समान उत्पाद में शामिल सहित) घरेलू उद्योग पर आधारित था । इस प्रकार, स्थापित कारणात्मक संबंध पीटीए के संबंध में अस्पष्ट और क्षीण रहा । उल्लेखनीय है कि देश में पीटीए के उत्पादक मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को नियमावली 1995 के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे पीटीए के आयातक हैं । लेकिन आरआईएल को इस कार्रवाई में संबंधित पक्षकार तथा पदत संरक्षण के पूर्णतया लाभग्राही के रूप में जारी रखा गया है । वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की परिभाषा से आरआईएल को शामिल करना या नहीं करना सुस्पष्ट रहा है और जाहिर है कि इसका आधार उनकी सुविधा है न कि केवल लागू कानून के उपबन्धों के अनुसार है ।

9. आईआरएसएल ने मै० आरआईएल को इस निर्णायक समीक्षा मामले में घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने पर विरोध प्रकट किया है, यद्यपि उन्हें मूल कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया था । मूल मामले की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आईआरएसएल यह समझते हैं कि ऐसी निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग की परिभाषा एक ऐसी कंपनी के हितों में पूर्णतया बदली नहीं जा सकती जिसे घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल ही नहीं किया गया है और अब उन सभी को, जो घरेलू उद्योग का अंग हों, उन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

10. आईआरएसएल यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मामला सीमा शुल्क अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के तहत आरंभ करके स्पष्ट रूप से उपर्युक्त धारा 9क(5) और

नियम 5(1) के उपबंध के विपरीत है और इससे एडीए 1995 के अनुच्छेद 11.4, अनुच्छेद 5.8 अनुच्छेद 3.2 तथा अनुच्छेद 3.7 का उल्लंघन होता है, इनके ब्यौरे अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं ।

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा मामला सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के उपबंधों के तहत आरंभ किया गया है, जो इस प्रकार है:-

क. इस धारा के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया गया हो, लगाए जाने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हुआ माना जाएगा;

ख. बशर्ते कि केन्द्र सरकार की एक प्रकार से यह राय हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति या इसके लागू बने रहने की संभावना रहती है । इसे समय समय पर पांच वर्षों की अगली अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसी अगली अवधि इस प्रकार बढ़ाई गई समयावधि के आदेश की तारीख से लागू होगी ।

ग. बशर्ते यह कि जहां कोई समीक्षा पांच वर्षों की उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले आरंभ की गई हो और उसे इस अवधि की समाप्ति से पहले पूरा नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसी समीक्षा के परिणाम आने तक लागू रहेगा ।

12. एडीए 1995 के तदनुरूपी उपबंध अनुच्छेद 11.3 में निर्दिष्ट है कि जो इस प्रकार है:- ' पैराग्राफ 1 तथा 2 का उपबंध नहीं होते हुए भी किसी निश्चित पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण उसके लागू होने से पांच वर्षों के बाद की तारीख (या पैराग्राफ 2 के तहत हाल ही समीक्षा की तारीख से बशर्ते समीक्षा में पाटन तथा क्षति दोनों को कवर किया गया हो, अथवा इस पैराग्राफ के तहत) से नहीं होगा जब तक कि प्राधिकारियों ने उस तारीख से पहले अपने आप की गई समीक्षा में निर्धारण नहीं किया हो अथवा उस तारीख से पहले यथोचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए अनुरोध से प्रमाणित शुल्क निर्धारित नहीं किया गया हो कि शुल्क समाप्त होने से पाटन तथा क्षति लागू रहने या उसकी पुनरावृत्ति होते रहने की संभावना है ।

13. उपर्युक्त धारा 9 क(5) तथा अनुच्छेद 11.3 के स्पष्टतया पाठन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 9क(5) के तहत मामला आरंभ करने से पहले केन्द्रीय सरकार को एक राय लेनी पड़ेगी जबकि अनुच्छेद 11.3 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारियों को यह तय करने की शर्त लगानी होगी कि शुल्क समाप्त करने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति जारी रखने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। सीमाशुल्क अधिनियम, 1995 तथा एडीए 1995 दोनों में प्राधिकारियों के लिए यह निश्चित कर्तव्य तय किए गए हैं कि वे मामला आरंभ करने से पहले जानकारी तथा साक्ष्यों की पर्याप्तता एवं विशुद्धता के आधार पर किसी राय/निर्णय पर पहुंचें।

प्रकटन विवरण-पत्र के बाद आईआरएसएल द्वारा किए गए निवेदन

14. प्रवर्तन, घरेलू उद्योग की स्थिति तथा समान उत्पादों के मुद्दे पर आईआरएसएल इस संबंध में पहले किए गए अपने निवेदन को दोहराना चाहते हैं और आगे टिप्पणी करते हैं कि डीजीएडी नियम 5(4) के उपबंधों की अनदेखी नहीं कर सकता है क्योंकि इस नियम में जांच आरंभ करने से पहले विशेष क्रियाविधि का अनुपालन करना होगा।

मैसर्स बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यु0 कं0 लिमिटेड, मुंबई के विचार

15. पाटनरोधी शुल्क लगने से पिछले साढ़े चार वर्षों में घरेलू उद्योग को अत्यधिक लाभ हुआ है। दिनांक 31 दिसंबर, 2001 तक की अवधि के दौरान पीटीए का कोई आयात नहीं हुआ। हमारा निश्चित तौर पर विश्वास है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देशों से आयात पूर्णतया बन्द हो गए हैं। ऐसा इस तथ्य के परिणामस्वरूप हुआ है कि संबद्ध देशों से होने वाले आयात उचित एवं अपाटित कीमतों पर प्रतियोगी नहीं हैं। अतः शुल्क हटाने से निर्यातक भारत को पाटित कीमतों पर निश्चित तौर पर अपने निर्यात आरंभ कर देंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी। इसलिए, हमारा अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहे। यह बात नोट की जाए कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद जांच अवधि में हानि हुई है।

घरेलू उद्योग - रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के विचार

16. आईआरएसएल द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग का दायरा मूल जांच से बदल नहीं सकता है। आगे यह श्क्ती कहा गया है कि चूंकि आरआईएल को मूल जांच में घरेलू उद्योग के दायरे से हटा दिया गया था, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह छूट नहीं है कि वह आरआईएल को घरेलू उद्योग का हिस्सा मान लें। नियम 2(ख) के तहत 'घरेलू उद्योग' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है - 'घरेलू

उद्योग' का अर्थ सामूहिक रूप से घरेलू उत्पादकों जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी भी क्रियाकलाप में लगे हों अथवा उनसे है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा हो। इसमें वह स्थिति शामिल नहीं है जब ऐसे उत्पादक तथाकथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा वे स्वयं उसके आयातक हों जिस मामले में (ऐसे उत्पादक माने जाएं) वे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हों।

17. स्मरण हो कि घरेलू उद्योग की परिभाषा में दिनांक 31 मई, 1999 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 44/99-सीशु(एनटी) द्वारा संशोधन किया गया था जिसमें शब्द 'गा/गे' के स्थान पर शब्द 'सकेगा' को शामिल किया गया था। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1998 के अपने अन्तिम जांच परिणाम में यह स्पष्ट किया गया था कि आर आई एल को घरेलू उद्योग के दायरे से हटा दिया गया क्योंकि वह जांच-अवधि के दौरान एक आयातक रहे। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि संगत समय पर कानून की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के दायरे से किसी भी आयातक को शामिल करने या हटाने के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, जिससे आयात किए गए।

18. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वे घरेलू उद्योग के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत निर्धारित परीक्षण की जांच करें क्योंकि वह ऐसी समीक्षा के समय मौजूद रहता है। कानून में प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया ऐसा कोई संकेत नहीं है कि क्षति-विश्लेषण को ऐसे घरेलू उद्योग तक ही सीमित रखना आवश्यक है जिन्होंने मूल जांच के लिए याचिका दायर की थी। आई आर एस एल ने कानून के किसी ऐसे उपबंध का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को मूल परिवादी के मात्र संदर्भ में निर्णायक समीक्षा जांच करने तक सीमित रखा गया हो। इस कानूनी स्थिति के अलावा, डब्ल्यूटीओ नामसूची निर्णयों के सम्पूर्ण विधि-संग्रह में यह सुझाव है कि क्षति-विश्लेषण, चाहे नवीन जांच में हो, घरेलू उद्योग के पर्याप्त हिस्से के लिए हो और उसे मात्र परिवादी तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

19. आई आर एल एल द्वारा एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत की गई निर्णायक समीक्षा घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(1) अथवा नियम 5(4) के तहत की गई शिकायत के आधार पर की गई है। आईआरएसएल द्वारा किए गए प्रवक्तव्यों को देखकर हमें आश्चर्य हुआ है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के पद पर आरोपीय वक्तव्य दिया गया है

जबकि विगत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आई आर एस एल लुँक छिपकर यह प्रयास कर रहे हैं कि परोक्ष उद्देश्यों के लिए तथ्य तैयार किए जाएं। हमारा अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे वक्तव्यों को गंभीरता से नोट करें।

२०. जहां तक आई आर एस एल द्वारा दी गई दलील की वैधता का संबंध है, हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा ९क(५) के उपबंधों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे उसमें उल्लेखित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करें। वास्तव में, ये शुल्क पांच वर्षों की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी (डी.ए.) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा ९क(५) के उपबंधों के तहत इसे और आगे बढ़ाने हेतु कार्रवाई नहीं करते। चूंकि इसकी जिम्मेदारी पूर्णतया निर्दिष्ट प्राधिकारी के ऊपर है, इसलिए, निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने हेतु अनुरोध किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग के लिए धारा ९क(५) में कोई उपबंध नहीं किया गया है। वास्तव में, आई आर एस एल के प्रतिनिधि ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा ९क(५) में नियम ५ के उपबंधों को पढ़ने का प्रयास किया है जबकि इस अधिनियम तथा नियमावली की वर्तमान योजना में ऐसे संबंध का कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारा सादर निवेदन है कि विधायिका का इरादा मूल रूप से स्पष्ट भाषा में देखा जाए, जिसका अर्थ यह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि क्या कहा गया है तथा क्या नहीं कहा गया है। यदि केवल घरेलू उद्योग के अनुरोध पर ही निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने का इरादा होता तो तब विधायिका ने धारा ९क(५) के तहत भी समीक्षा मामले में लागू नियम ५ के उपबंध स्पष्टतया किया होता। इस प्रकार, धारा ९क(५) "निर्णायक समीक्षा" अथवा "अन्तिम समीक्षा" के संबंध में एक स्वतः स्पष्ट उपबंध है और जैसाकि आई आर एस एल का ध्येय है नियम ५(१) अथवा नियम ५(४) का कोई संबंध नहीं है।

२१. जैसाकि ऊपर कहा गया है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा ९क(५) के तहत निर्णायक समीक्षा के अधिकार एवं दायित्व केवल डीए को है जैसाकि विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा से विदित है। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी का स्वविवेक है कि वे पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करें अथवा नहीं।

२२. वर्तमान मामले में याद रहे कि डीजीएडी ने अपने दिनांक २७ मार्च, २००२ के पत्र द्वारा पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ९क(५) के तहत समीक्षा की आवश्यकता के संबंध में आर

आई एल से टिप्पणियां मांगी थी। आर आई एल ने अपने दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के पत्र द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत यथोचित निष्कर्ष देने हेतु डीए की सहायता के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी वाले प्रपत्र में अपने हित की सूचना दी। तत्पश्चात् डी ए ने धारा 9क(5) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 मई, 2002 की अधिसूचना के तहत समीक्षा आरंभ की। घरेलू उद्योग के एक हिस्से के रूप में आर आई एल ने दिनांक 22 मई, 2002 की प्रारंभिक अधिसूचनाओं के पैरा 6 में मांगी गई जानकारी डीए को प्रस्तुत की जिससे डीए शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की जांच कर सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि आई आर एस एल स्वयं यह मानने में इस भ्रम में पड़ गए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच के प्रत्युत्तर में आर आई एल के इच्छा पत्र अथवा पहल-अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत जानकारी को शिकायत के रूप में माना जा सकता है। वास्तव में, धारणा की असंगतित इस तथ्य से कुछ अधिक है कि तथाकथित शिकायत निर्णायक समीक्षा आरंभ होने के बाद प्रस्तुत हुई है। दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के पत्र डीए के कार्यालय से उस प्रपत्र के संसंबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसमें जानकारी दी जानी है और यह रुचि व्यक्त करनी है कि डी ए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत समीक्षा करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यह बात भी नोट करनी रुचिकर है कि आईआरएसएल ने दिनांक 1 नवंबर, 2002 के लिखित निवेदन (पैरा 2.09 तथा 2.10) में स्वयं कहा है कि उक्त लिखित निवेदन के प्रारंभिक पैराग्राफों में प्रस्तुत प्रकथनों के बिल्कुल विपरीत घरेलू उद्योग द्वारा कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है। उपर्युक्त आधार वाक्यों में आई आर एस एल का वर्तमान पहले के संदर्भ में 'गैर-कानूनी' बताना अपने-आप में व्यंग्यात्मक रूप से पूर्णतया कानूनी आधार-विहीन और वास्तविक अर्थ-विहीन है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी द्वारा यह बात पुष्ट है कि उन्होंने दिनांक 22 मई, 2002 को यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णायक समीक्षा आरंभ की है। प्राधिकारी को स्मरण है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(i)(ड.) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करें।

24. कुछ इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई इस टिप्पणी के संबंध में कि समीक्षा के लिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-5 की जरूरत पूरी की जाए, प्राधिकारी को याद है कि यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों के तहत निर्मित

पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(3) के तहत नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 तथा 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। इस उपबंध में नियम 5(1) शामिल नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि जहां तक समीक्षा का संबंध है, नियम 5(1) तथा नियम 23 में संयोजन नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह बात नोट की जाती है कि जहां तक 'निर्णायक समीक्षा' अथवा 'अन्तिम समीक्षा' का संबंध है, धारा 9क(5) एक स्वतःस्पष्ट उपबंध है और इसका नियम 5(1) अथवा नियम 5(4) से कोई संयोजन नहीं है, जैसाकि आईआरएसएल द्वारा किया जा रहा है। पाटनरोधी करारों के अनुच्छेद 11.3 के अनुसार, 'पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई भी निश्चित पाटनरोधी शुल्क उसके लागू होने की तारीख (अथवा पैराग्राफ 2 के तहत अद्यतन समीक्षा, यदि पाटन तथा क्षति दोनों ही उस समीक्षा में कवर किए गए हों, अथवा इस पैराग्राफ) से अधिकतम पांच वर्षों के भीतर किसी तारीख को समाप्त होगा, बशर्ते प्राधिकारी अपनी पहल की तारीख से पहले अथवा उस तारीख से पहले की यथोचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर आरंभ समीक्षा में यह तय नहीं करें कि शुल्क समाप्त करने से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

25. अतः उपर्युक्त प्राप्ति के अनुसार यह देखा गया है कि निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी की मुख्य टिप्पणी अपनी पहल पर यह जांच करने के बारे में है कि शुल्क समाप्त कर देने से पाटन तथा क्षति जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस मामले में प्राधिकारी ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2002 के पत्र में आर आई एल (जिन्हें पिछली मध्यावधि समीक्षा के दौरान घरेलू उद्योग माना गया) से कतिपय जानकारी मांगी थी। आर आई एल ने दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के अपने पत्र द्वारा डीए को सूचित किया कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी खा जाए। उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा जानकारी देने के प्रपत्र के संबंध में भी पूछताछ की ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत उपर्युक्त जांच परिणाम तय करने में डीए को सहायता मिल सके। तत्पश्चात्, डीए ने धारा 9क(5) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 मई, 2002 की अधिसूचना द्वारा समीक्षा आरंभ की।

26. वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि प्राधिकारी ने धारा 9क(5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समीक्षा की है। मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि० (आर आई एल) को यद्यपि मुख्य जांच में घरेलू उद्योग के दायरे से हटा दिया गया था, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के संदर्भ में इस मामले में इच्छुक पक्षकार माना गया। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग का अर्थ समान

वस्तु के विनिर्माण तथा किसीमें कार्यरत सामूहिक रूप में घरेलू उत्पादकों से है ।" यहां प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा विनिर्मित पीटीए को संबद्ध देशों से भारत में आयातित पीटीए के समान वस्तु के रूप में लिया जाए । प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि मैसर्स आर आई एल ने जांच अवधि (पीओआई) के दौरान कोई आयात नहीं किया और यह भी पाया गया है कि मैसर्स आरआईएल संबद्ध माल-पीटीए का सबसे बड़ा उत्पादक (घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक उत्पादन) है और प्राधिकारी ने उन्हें पिछली मध्यावधि समीक्षा में घरेलू उद्योग के रूप में माना है । अतः प्राधिकारी मैसर्स आरआईएल को इस निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग मानते हैं ।

पाटन:

आयातक मैसर्स आईआरएसएल के विचार

27. निर्णायक समीक्षा के अवैधानिक शुरू होने की दलील के पूर्वाग्रह बिना आई आरएसएल चाहते हैं कि इस मामले के गुणावगुण तथा सम्पोषण पर विचार किया जाए और निवेदन करते हैं कि आर आई एल द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2002 को दायर प्रश्नावली-उत्तर के अनुसार यह दो स्वीकरण बनते हैं-

- (i) कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का उन देशों से कोई आयात नहीं किया गया जिनके विरुद्ध मामला चल रहा है अर्थात् कोरिया, थाइलैण्ड तथा इण्डोनेशिया, और
- (ii) इसके अलावा, आरआईएल ने यह भी स्वीकार किया कि जांच-अवधि के दौरान किसी अन्य देश से भी संबद्ध उत्पाद का आयात नहीं किया गया । आरआईएल ने यह भी पुष्टि की कि जांच-अवधि के पहले जो भी आयात किए गए थे वे अग्रिम लाइसेंस पर किये गए और उससे घरेलू उत्पादकों को कोई वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं हुई है ।

28. जैसाकि आर आईआईएल ने स्वयं यह बात स्वीकार की कि चूंकि जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किया गया, अतः ऐसा कोई पाटन जारी नहीं है जिससे तथाकथित याचिकाकर्ता के आदेश पर डीजीएडी द्वारा चयनित जांच अवधि के दौरान क्षति हुई हो । इन देशों से जांच के अधीन उत्पाद का आयात शून्य रहा जो नियम 14(घ) के उपबंधों के तहत कम है ।

29. इन मामले के तथ्यों के चलते जांच का नियमावली, 1995 के नियम 14(घ) द्वारा यथा निर्धारित अनुसार समाप्त होना अपेक्षित है ।

30. आई आर एस एल यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि लो कार्बन फेरो क्रोम (एलसीएफसी) के मामला सं० 44/1/99-डीजीएडी के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं यह तय किया था कि जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं होने से न तो वह जारी है और न ही पाटन की पुनरावृत्ति की ही कोई आशंका है और इसलिए, इस मामले का समर्थन नहीं किया जा सकता है ।

31. सम्पूर्ण मामला, उसके आरंभ के समय पर्याप्तता तथा विशुद्धता की जांच योग्य किसी जानकारी अथवा साक्ष्य के बिना ही कल्पना, पूर्वधारणा तथा इच्छापूर्ण सोच के आधार पर चलाया गया है । इसके मुख्य कारण निम्नानुसार हैं-

- (i) कि संबद्ध देशों से पर्याप्त आयात होंगे (कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया) ।
- (ii) कि संबद्ध देशों से इन आयातों की कीमतें आवश्यक रूप से पाटित कीमतें होंगी (कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया) ।
- (iii) कि संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग पर कारणात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे ऐसे आयातों के कारण क्षति होगी (कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया) ।
- (iv) कि या तो अन्य देशों से कोई आयात नहीं होंगे अथवा यदि आयात हुए भी तो वे अपाटित कीमतों पर होंगे या घरेलू उद्योग पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा (कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया) ।

घरेलू उद्योग-मैसर्स आरआईएल के विचार

32. यद्यपि इस उत्पाद का पाटन करने वाले इन उत्पादकों के ठीक-ठीक लागत ब्यौरे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं किन्तु ये व्यापार भेद हैं और इनका खुलासा नहीं किया जाता है । मैसर्स डेविट एण्ड कं० (यूएसए) द्वारा किए गए विश्वव्यापी पीटीए विनिर्माण लागत विश्लेषण के आधार पर जांच अवधि के लिए पीटीए के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाता है । यद्यपि डेविट एण्ड कं० द्वारा किए गए लागत-अध्ययन वर्ष

1997 के हैं किन्तु दो प्रमुख कच्चे मालों अर्थात् पैराक्सीन तथा ऐसेटिक एसिड की लागत को छोड़कर शेष कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

33. आईआईएल ने पीटीए आयात के संबंध में पत्नों से आंकड़े प्राप्त किए हैं । यह नोट करना रुचितकर है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में पीटीए का कोई आयात नहीं किया गया है । कुछ आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए तो गए हैं लेकिन वे इस तथ्य के मद्देनजर इस समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संगत नहीं हैं कि अग्रिम लाइसेंस पर आयातित पीटीए पाटनरोधी शुल्कों के अध्वधीन नहीं हैं क्योंकि वे देश के व्यापार में शामिल नहीं हुए हैं ।

34. कृपया यह देखा जाए कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अधिकतम समयावधि पांच वर्षों तक सीमित रखी जाए। किन्तु, इस उपधारा (5) के उपबंध के अनुसार डीए चाहें तो वे ऐसे अर्थदण्ड की अवधि समय-समय पर अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं बशर्ते किसी समीक्षा में यह राय हो कि इस शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन तथा क्षति जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होती रहने की संभावना है । इस धारा में हम संबद्ध देशों में होने की भारी निर्यातयोग्य बेशी संबंधी जानकारी प्रदान कर रहे हैं जिससे स्पष्ट रूप से यह इंगित होगा कि पाटनरोधी शुल्क हटा देने से वह माल भारत में स्थान पा लेगा ।

35. यहां हम यह भी बता देना चाहेंगे कि यह तथ्य कि संबद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान पीटीए का कोई भी आयात नहीं हुआ, स्वयं यह बात इंगित करता है कि इन देशों में कीमतें अप्रतिस्पर्धी प्रकार की हैं । संबद्ध देशों से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने के फलस्वरूप निश्चित रूप से पाटन की पुनरावृत्ति होगी । सादर निवेदन है कि यह तथ्य कि जांच-अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है, कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि डीए को केवल इस बात की जांच करनी है कि 'पुनरावृत्ति का परीक्षण' क्या है जो वर्तमान मामले में पर्याप्त संतोषजनक है ।

निर्यातक -मैसर्स पीटी पोलीप्राइमा कार्यारेक्सा के विचार

36. हम यह निवेदन दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 को उद्योग भवन में सार्वजनिक सुनवाई के बाद पीटी पोलीप्राइमा कार्यारेक्सा की ओर से कर रहे हैं ।

37. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम ('अधिनियम') जिसका आविर्भाव डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार ('करार') के अनुच्छेद 11 से हुआ, कि धारा 9 के में यह प्रावधान है

कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जान से पांच वर्षों की समयावधि समाप्त होने पर, समाप्त हो जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार की किसी समीक्षा में यह राय नहीं है कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

38. यह संभव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इस समीक्षा में यह राय बना सके कि इण्डोनेशिया से पीटीए के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी । इण्डोनेशिया से वर्ष 1999 से पीटीए का कोई भी आयात नहीं हुआ है और केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सकारात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित कर सके कि यह संभावना हो कि इण्डोनेशिया से आयातों की पुनरावृत्ति होगी और मात्र यह संभावना हो कि पाटनरोधी शुल्क के नहीं होने पर इण्डोनेशिया से पाटित कीमतों पर आयातों की पुनरावृत्ति होगी । ऐसा कोई यथोचित आधार नहीं है जिस पर केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो सके कि इण्डोनेशिया से पाटित आयातों की पुनरावृत्ति पाटनरोधी शुल्क के अभाव में होने की संभावना है । यह बात कि इण्डोनेशिया से संबद्ध माल के आयात की पुनरावृत्ति हो सकती है, मात्र एक निराधार कल्पना है और इसका कोई तथ्यपरक आधार नहीं है ।

39. घरेलू उत्पादक रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि० ने इस समीक्षा के लिए दिए गए लिखित निवेदन और सार्वजनिक सुनवाई में की गई प्रस्तुति में स्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है किन्तु उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में किसी परिवर्तन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है जिससे केन्द्रीय सरकार ऐसी यथोचित राय तैयार करे कि इण्डोनेशिया से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । अधिनियम तथा करार की भाषा से बहुत ही स्पष्ट है कि ऐसी प्रदर्शित संभावना अवश्य होगी कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन की पुनरावृत्ति होगी । यह काफी नहीं है कि इस बात की अप्रत्यक्ष संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में पाटन बार-बार होगा ।

40. रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि० यह स्वीकार करते हैं कि यह तथ्य कि जांच-अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुए, कोई महत्व नहीं है और "पुनरावृत्ति का परीक्षण" से पर्याप्त रूप से संतुष्टि नहीं है । यह बात नोट करने योग्य है कि इण्डोनेशिया से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के तुरन्त बाद दो वर्षों में जारी रहे किन्तु विगत तीन वर्षों में इण्डोनेशिया से कोई आयात नहीं हुए । अतः यह बात मानी नहीं जा सकती कि पाटनरोधी शुल्क से ही इण्डोनेशिया से होने वाले आयात समाप्त हो गए ।

41. यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि मूल जांच जिसमें पाटनरोधी शुल्क लगाया गया, में याचिकाकर्ता मैसर्स बॉम्बे डाइंग ने इस समीक्षा में कोई निवेदन नहीं किया है और सार्वजनिक सुनवाई में किसी अन्य पक्षकार के आदेश पर उपस्थित हुए ।

42. सारांश में केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे ऐसी यथोचित राय बने कि इण्डोनेशिया से संबद्ध माल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से इण्डोनेशिया से पाटन कीमतों पर उक्त माल के आयातों की पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी । यह बात कि इण्डोनेशिया से संभाव्यतः आयातों में पुनरावृत्ति होगी, मात्र एक निराधार कल्पना है ।

प्रकटन विवरण-पत्र पर मैसर्स पोलीप्राइमा कार्यारेक्सा की टिप्पणी

43. निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग अपने इस दावे के समर्थन में ऐसी वास्तविक प्रदान नहीं कर सका कि पाटनरोधी उपायों के अभाव में इण्डोनेशिया से पाटित कीमतों पर आयातों की पुनरावृत्ति होती रहेगी । वे स्वीकार करते हैं कि ' संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से निश्चित रूप से पाटन की पुनरावृत्ति होगी ' किन्तु यह कुछ नहीं बल्कि उनकी स्वीकृति का शब्दांडबल है । पाटन की पुनरावृत्ति के संबंध में घरेलू उद्योग का मामला इस स्वीकृति पर आधारित प्रतीत होता है कि संबद्ध देशों में भारी निर्यात योग्य बेशी जमा है और जांच की अवधि के दौरान भारत को इस उत्पाद का कोई निर्यात किया गया है । इससे पक्के तौर पर यह प्रदर्शित होता है कि पाटनरोधी उपायों के अभाव में पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है । हम प्राधिकारी के इस विचार में शामिल होते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन की पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं है । हमारा विश्वास है कि इस विचार से यह निष्कर्ष बनेगा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन की पुनरावृत्ति होगी ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

पाटन

44. प्राधिकारी ने 9क(1) ग के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पीटीए के ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक-प्रश्नावली भेजी । किन्तु, मुख्य जांच में उल्लिखित किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया । अतः प्राधिकारी का यह निर्णय है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने नियमावली में यथा प्रावधानानुसार

प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया। प्राधिकारी का यह भी निर्णय है कि पीटीए का सामान्य मूल्य स्थापित करने की मूल जिम्मेवारी प्राधिकारी से सहयोग करने में असफल निर्यातकों/उत्पादकों की है।

45. प्राधिकारी ने पीटीए के ज्ञात आयातकों को भी आयातक-प्रश्नावली भेजी। उनमें से केवल एक आयातक-मर्सर्स इण्डोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर भेजा है।

46. जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक/आयातक ने संबद्ध देशों से संबद्ध माल के कोई निर्यात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग का यह दावा नोट करते हैं कि जांच-अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध देशों से पीटीए का कोई भी आयात नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी कहा है कि अग्रिम लाइसेंस पर कुछ आयात हुए हैं जो इस तथ्य के मद्देनजर समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संगत नहीं हैं कि अग्रिम लाइसेंस पर आयातित पीटीए पाटनरोधी शुल्कों के अध्वधीन नहीं हैं क्योंकि यह आयात देश के व्यापार में नहीं आते हैं।

47. वर्तमान जांच के लिए डीजीसीआईएण्डएस को एक ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों के ब्यौरे प्रदान किए जाएं। डी जी सी आई एण्ड एस ने भी अब यह पुष्टि कर दी है कि जांच-अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पीटीए का कोई भी आयात-व्यापार नहीं किया गया।

48. डीजीसीआईएण्डएस द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और उद्योग के दावे का अध्ययन करने के पश्चात् प्राधिकारी इस बात का समापन करते हैं कि जांच-अवधि के दौरान भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध माल के कोई भी निर्यात किया गया है। संबद्ध देशों से निर्यात नहीं होने पर प्राधिकारी का यह प्रस्ताव नहीं है कि जांच-अवधि के दौरान भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध माल की औसत निर्यात कीमत का आकलन किया जाए।

49. अतः प्राधिकारी इस विषय पर यह निर्णय देता है कि ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के कारण पाटन की पुनरावृत्ति अन्तिम नहीं है और इसलिए यह नहीं मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध माल के संबंध में सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करना उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी का यह विचार है कि चूंकि जांच-अवधि के दौरान भारत के संबद्ध देशों से संबद्ध माल का कोई निर्यात नहीं हुआ है, इसलिए, संबद्ध माल का कोई

पाटन नहीं हुआ है और जांच-अवधि के दौरान भारत को संबद्ध माल की निर्यात-कीमत के अभाव में प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-6 में विहित सिद्धांत के अनुसरण में पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

क्षति

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

50. जैसाकि इंगित किया गया है, निर्णायक समीक्षा में डीए द्वारा लागू अपेक्षित परीक्षण की सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति जारी रहने की संभावना की जांच की जाए। अतः निर्णायक समीक्षा के मामले में वास्तविक क्षति के मूल्यांकन हेतु मातबण्डों तथा परीक्षणों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में डीए का ध्यान चीन जनवादी गणराज्य से आईबीबी के मामले (हवाला 2001(127) ईएलटी 629 (ट्राइ-डेल) में माननीय सीगैट के निर्णय की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। किन्तु, चूंकि डीए द्वारा निर्णायक समीक्षा मामले के लिए अलम से कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है, इसलिए, हम प्रपत्र-iv क में अपेक्षित जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस बात के होते हुए भी हमारा मूल निवेदन कि किसी निर्णायक समीक्षा के लिए नए मामलों के वास्ते आवेदन-प्रपत्र उपर्युक्त नहीं है, इसलिए हम वास्तव में डीए के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि संबद्ध देशों से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है।

51. घरेलू उद्योग ने जांच-अवधि के दौरान पीटीए की बिक्री *** रू० प्रति एमटी की औसत कीमत पर की है। घरेलू उद्योग मौजूदा कीमत स्तर कायम रख सका है। इसका मूल कारण यह है कि पाटनरोधी शुल्क कायम रहे हैं। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मानदण्डों की दृष्टि से देखा जा सकता है जैसाकि इंगित किया गया है।

52. जबकि जांच-अवधि के दौरान वार्षिक उत्पादन वर्ष 2000-01 में *** / एमटी से बढ़कर *** / एमटी हो गया, इसलिए घरेलू उद्योग अब भी *** % के उच्च उपयोगिता-स्तर पर प्रचालन करता रहा है। जहां तक बिक्री-मात्रा का संबंध है, बिक्रियों में मूल्य की दृष्टि से पर्याप्त वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग निबल बिक्री वसूली के कम रहते हुए भी अपनी बिक्री पर कुछ लाभ कमा सका है जिसके परिणामस्वरूप लाभ का स्तर भी कम रहा है।

इंडोनेशिया, थाईलैण्ड तथा कोरिया से पीटीए के आयात		
	मात्रा (मी.टन)	सीआईएफ \$ /मी.टन
99-00	2021	422
00-01	3955	456
2001-02	शून्य	शून्य

53. वर्तमान समीक्षा के परिणामस्वरूप, ऐसे निराशाजनक नतीजे में कि पाटनरोधी शुल्क वापस लिए गए हैं कि संबद्ध देशों से आयातित पीटीए की कीमतें पाटनरोधी शुल्कों के भारत की सीमा से भी कम रहेंगी। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उद्योग को भी अपनी कीमतें उतने ही नीचे लानी जरूरी होगी जिससे इस उद्योग का सम्पूर्ण लाभ मात खा जाएगा। इससे घरेलू उद्योग ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जो पाटनरोधी शुल्क लगने से पहले था।

54. जांच अवधि के दौरान आर आई एल की संभावित उचित कीमत उसके पूंजीनिवेश पर यथोचित आय पर *** रू० /एम टी आकलित होती है। पाटनरोधी शुल्क के वापस लेने से निश्चित रूप से कीमत मंदी, कीमत गिरावट तथा अथवा यथोचित लाभ की संभावित हानि, अथवा गंभीर हानि हो सकेगी जो संबद्ध देशों से पीटीए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने हेतु न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं।

घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जानकारी			
मानदण्ड वर्ष	99-00	00-01	पीओआई(ए)
स्थापित क्षमता सूचकांक	100	100	100
उत्पादन सूचकांक	100	101	99
क्षमता उपयोगिता सूचकांक	100	101	99
विक्री घरेलू सूचकांक	100	86.15	90.86
निर्यात विक्री सूचकांक	100	296.32	184.43
कैप्टिव खपत सूचकांक	100	98.57	73.81
प्रारंभिक स्टॉक सूचकांक	100	79.12	76.62421
अन्तिम स्टॉक सूचकांक	100	96.85	100.8838
लाभ सूचकांक	100	101.7391	81.01726
रोजगार सूचकांक	100	100	100
बाजार-हिस्सा सूचकांक	85%	79%	73%

प्रकटन के बाद घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

55. इस संबंध में हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि हमने पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने संबंधी अपने मामले को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त आंकड़े तथा अकाट्य तर्क दिए हैं। इस संबंध में हमने विधि-संग्रह भी प्रस्तुत किया जैसाकि यूरोपीय संघ तथा पीटीए में प्रणाली विकसित हुई है। इससे यह तथ्य स्पष्टरूप से उभर कर सामने आता है कि इससे ठीक पहले की अवधि में संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं किए गए, यह निष्कर्ष बनाने का आधार नहीं हो सकता है कि शुल्क आगे बढ़ाने का कोई मामला नहीं है। हमारा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध है कि वे कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले सार्वजनिक सुनवाई के समय किए गए हमारे सभी निवेदनों और दिनांक 17 जनवरी, 2003 को दिए गए अतिरिक्त निवेदनों को कृपया स्वीकार कर लें।

आयातक मैसर्स इण्डो रामा सिंथेटिक्स (इं.) लि० द्वारा किए गए निवेदन

56. आईआरएसएल यह निवेदन करना चाहते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उपाय स्वभावतः संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्धारित नहीं है जब तक कि पाटित कीमतों पर हो रहे या संभावित काफी आयातों का वास्तविक साक्ष्य नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो। यह उपाय मात्र अनुमानों, निराधार कल्पनाओं, पूर्व धारणाओं और बिना वास्तविक साक्ष्यों युक्त आरोपों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

57. निवेदन है कि आर आई एल द्वारा ऐसे कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे पाटन अथवा क्षति की पुनरावृत्ति पर परोक्ष संबंध हो सके। संभावित वास्तविक साक्ष्य आदेश, दरें, तथाकथित देशों से आयात-बीजक अथवा जांच हो सकते हैं। इन सभी वास्तविक साक्ष्यों के अभाव में पुनरावृत्ति की पूर्वधारणा केवल इच्छा एवं कल्पना है।

58. यदि पीटीए को स्वतंत्र उत्पाद के रूप में अलग से माना जाता जिसकी डीजीएडी ने सुनवाई के द्वारा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में घोषणा की थी, तब मामले के आरंभ के समय क्षमता जो *** लाख एमटी थी, बढ़कर *** लाख एमटी हो गई, इस प्रकार प्रतिष्ठापित क्षमता में *** % की वृद्धि परिलक्षित होती है। उत्पादन *** लाख एमटी से बढ़कर *** लाख एमटी हो गया। इसमें *** % की अद्भुत वृद्धि हुई। इसी अवधि में क्षमता उपयोग ***% से बढ़कर ***% हो गई जिसमें

*** % की वृद्धि प्रदर्शित है। वास्तव में, पीटीए का उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में अपेक्षातया अधिक बताया गया है।

59. पाटनरोधी शुल्कों की अवधि अर्थात् अप्रैल, 1998 से अक्टूबर, 2002 तक की अवधि के दौरान कीमत मोर्चे पर पीटीए की प्रति किग्रा. कीमत *** ₹0 प्रति किग्रा. से बढ़कर *** ₹0 प्रति किग्रा. हो गई। इस प्रकार इसमें *** % की वृद्धि दर्शाई गई जबकि प्रदत्त संरक्ष *** % से *** % हो गया। जांच-अवधि के दौरान कीमत-वृद्धि (जांच अवधि के दौरान औसत कीमत *** ₹0 प्रति किग्रा. रही) पाटनरोधी शुल्क लगने की अवधि की तुलना में अधिक रही। यह कीमत-तुलना आरआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कीमत-सूची पर आधारित है। यह सभ्नी वास्तविक साक्ष्य घरेलू उद्योग की पर्याप्त वृद्धि तथा शक्ति की ओर इंगित करते हैं जिसके अनुसार पुनरावृत्ति की इच्छित आशंका कुछ नहीं बल्कि रस्तीभर साक्ष्य बिना दिवास्वप्न से ज्यादा नहीं है और इसलिए, इस कारण यह मामला समाप्त करने योग्य है।

60. प्रकटन विवरण-पत्र के बाद मैसर्स आईआरएसएल के विचार:

जांच अवधि के दौरान न तो कोई पाटन हुआ और भविष्य में पाटन की पुनरावृत्ति होने के अवसर भी नहीं हैं। जांच-अवधि के दौरान कोई क्षति स्थापित नहीं हुई है और क्षति की पुनरावृत्ति के पूर्वानुमान कोई अवसर भी नहीं है अथवा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II और अनुबंध-III के उपनियम vii के अनुसार अन्य कारक भी सिद्ध नहीं हुए। घरेलू उद्योग द्वारा किया एकमात्र निराधार निवेदन किसी तथ्यों के प्रमाण के बिना भारी निर्यात योग्य बेशी माल का दोषारोपण है जिसकी पूछताछ, क्रयादेश, रुचि अभिव्यक्त, पुष्टादेश, एल सी तथा संबद्ध दस्तावेजों जैसे भारत को निर्यात की संभावना हो। एकमात्र दोषारोपण, निराधार कल्पना यह है जिसकी बिल्कुल कम संभावना है। तथ्य यह है कि पाटनरोधी शुल्कों तथा सीमाशुल्कों में कटौती के बावजूद भारत को पीटीए का कोई निर्यात नहीं किया गया। उपर्युक्त के चलते आईआरएसएल पहले ही किए गए निवेदनों को दोहराते हुए निवेदन करते हैं कि इस जांच से कोई वास्तविक आशंका अथवा क्षति की पुनरावृत्ति समाप्त हो जाएगी।

मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कारपोरेशन प्राइवेट लि0 के विचार:

61. पीटीए का कीमत में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार, दोनों में अगस्त, 2002 से गिरावट का रुख रहा है। अगले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 4 मिलियन टन

अतिरिक्त पीटीए उपलब्ध हो जाएगा। इसका कारण यह है कि नए संयंत्र लगेंगे और नए संयंत्रों में क्षमता विस्तार होगा। उससे भारत के पीटीए उत्पादकों को क्षति होने की आशंका है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्कों के प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप पाटन तथा गंभीर क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

प्रकटन के पश्चात् मैसर्स एमसीसी पी टी ए इण्डिया कार्पो० प्रा० लि० के विचार

62. क्षमताओं में हाल की वृद्धि से पीटीए की सप्लाई में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तदनुरूपी मांग में अधिवृद्धि हुई है। पीटीए के प्रमुख आयातक बाजार - चीन के पोलिएस्टर विनिर्माताओं द्वारा मार्च, 2003 से वांछित कार्यचालन कटौती से बाजार असंतुलन और भी बिगड़ गया। वहां वर्ष 2002 में 4 मिलियन टन से भी अधिक आयातित पीटीए की खपत हुई। चीन में पीटीए की मांग में इस कमी के फलस्वरूप एशियाई बाजार में पीटीए की भारी मांग आ रही है और घरेलू बाजार में पाटन की आशंका बढ़ गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

63. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के अनुसार ' इस धारा के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क का, जब तक कि पहले प्रतिसंहरित नहीं किया गया हो, ऐसे अर्थदण्ड की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा:

आगे यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार की किसी समीक्षा में यह राय है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने और क्षति होने की संभावना है, तो वे समय-समय पर उसे पांच वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और वह अतिरिक्त अवधि समयावधि बढ़ाए जाने संबंधी आदेश की तारीख से लागू होगी:

बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले आरंभ समीक्षा का ऐसी समाप्ति से पहले समापन नहीं हो गया हो तो पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष से अनधिक अगली अवधि के लिए ऐसी समीक्षा का परिणाम आ जाने तक प्रवृत्त रहेगी।'

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति के निष्कर्ष का निर्णय हो जाए तो ऐसे निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण शामिल होगा जिसमें संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल हैं।' कीमतों पर पाटित

आयातों के प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में काफी कटौती रही है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतें काफी स्तर तक गिर जाएंगी अथवा कीमत वृद्धि रूकेगी जो अन्यथा काफी सीमा तक होंगी ।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोगिता, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा तथा मार्जिन, आदि के रूप में उद्योग की स्थिति संबंधी आंकड़ों पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसार विचार किया गया ।

चूंकि वर्तमान जांच के तहत इस बात का मूल्यांकन किया जाना है क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन जारी रहने तथा पुनरावृत्ति और क्षति होने की संभावना होगी, इसलिए प्राधिकारी ने इस पहलू के मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-ii (iv) में इंगित क्षति मानदण्डों को उपयुक्त समझा है ।

64. निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करनी अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क समाप्त कर देने से पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति और क्षति होने की संभावना है । अतः घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की उसके जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति के संदर्भ में जांच करना जरूरी है । इसके अलावा, प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करते समय ध्यान में रखना जरूरी है ।

65. प्राधिकारी ने, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग तथा आयातक द्वारा किए गए निवेदनों का अध्ययन कर दिया है । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान किसी भी संबद्ध देश से संबद्ध माल का कोई आयात नहीं किया गया है । इस तथ्य को देखते हुए प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि इन अवधियों में घरेलू उद्योग को कोई भी मात्रा-क्षति नहीं हुई है ।

66. घरेलू उद्योग-मैसर्स आरआईएल ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग वर्तमान कीमत-स्तर मूल रूप से पाटनरोधी शुल्कों के बने रहने के कारण कायम रख सका है । घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उनकी बिक्री-मात्रा में वृद्धि हुई है यद्यपि मात्रा की दृष्टि से बिक्री में गिरावट आई है । उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध माल की संभावित उचित कीमत की गणना *** रू0/एमटी

पर की गई है और पाटनरोधी शुल्कों को वापस ले लेने से निश्चित तौर पर मंदी, रोक, यथोचित लाभ की संभावित हानि अथवा भारी हानि संबद्ध देशों से पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने को न्यायोचित ठहराने हेतु पर्याप्त हैं।

67. जहां तक कीमत-क्षति का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विभिन्न क्षति-मानदण्डों की जांच की है।

(i) आयात-मात्रा तथा बाजार हिस्सा: घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया कि संबद्ध देशों से जांच-अवधि के दौरान संबद्ध माल का कोई आयात नहीं किया गया। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएण्डएस द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार संबद्ध देशों से किए गए आयात-मात्रा की जांच की और यह निष्कर्ष देते हैं कि जांच-अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध माल का कोई आयात नहीं हुआ है। प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह बात नोट की जाती है कि जांच-अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार-हिस्सा वर्ष 1999 के 80% से घटकर 64% रह गया। जांच अवधि और उससे पहले दो वर्षों के दौरान संबद्ध माल की मांग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। मांग की गणना करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्रियां, अन्य उत्पादकों के उत्पादन-आंकड़ों, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं (अन्य उत्पादकों कोई संगत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं) और भारत में आयात-मात्रा के आंकड़ों को शामिल किया है।

बाजार हिस्सा			
	99-00	00-01	2001-02ए)
घरेलू उद्योग %	80.92%	69.97	64.98
अन्य उत्पादक %	14.61	29.01	35.01
आयात%	4.47	1.01	0

(ii) क्षमता उपयोग: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच-अवधि में क्षमता-उपयोग में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध माल की क्षमता उपयोगिता जांच-अवधि और विगत वर्षों में अधिक रही है।

- (iii) उत्पादन: संबद्ध माल के उत्पादन में जांच-अवधि में विगत अवधियों की तुलना में मामूली सुधार दर्शाया गया है। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग जांच-अवधि तथा विगत वर्षों के दौरान अधिक उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त कर सका है।
- (iv) बिक्री मात्रा:- मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से जांच अवधि के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट रही है। उनमें 1999-2000 से 2000-01 तक मात्रा में *** % और मूल्य में *** % की गिरावट रही। किन्तु बिक्री मात्रा की दृष्टि से *** % की वृद्धि दर्शाई गई है।
- (v) निर्यात: घरेलू उद्योग मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से जांच अवधि के दौरान वर्ष 1999-2000 की तुलना में काफी निर्यात वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर सका है। वास्तव में, घरेलू उद्योग में, निर्यात बिक्री में वर्ष 1999-00 की तुलना में मात्रा की दृष्टि से *** % और मूल्य की दृष्टि से *** % की वृद्धि दर्शाई गई।
- (vi) प्रारंभिक स्टॉक तथा अन्तिम स्टॉक: प्रारंभिक स्टॉक में जांच अवधि के दौरान वर्ष 1999-00 की तुलना में काफी गिरावट रही है जबकि अन्तिम स्टॉक में अधिकतर वही रहा।
- (vii) लाभ/हानि: घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच-अवधि के दौरान वर्ष 1999-00 की तुलना में गिरावट रही।

68. प्राधिकारी ने क्षति तथा पीटीए आयातों पर मौज्जा पाटनरोधी शुल्क के संबंध में उपर्युक्त आंकड़ों को शामिल किया है, जब निर्णय करने के लिए यह अन्तिम निर्धारण किया कि क्या मौज्जा पाटनरोधी शुल्क हटाने से पाटन तथा क्षति जारी रहेगी अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी।

घरेलू उद्योग के लिए समान उत्पादों हेतु, गैर-क्षति कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने संबद्ध माल की वास्तविक उत्पादन-लागत का प्रयोग किया है जिससे घरेलू उद्योग के लिए अनुकूल उत्पादन-लागत का निर्धारण किया जा सके जिसमें कच्चे माल के मानकीय सर्वोत्तम खपत मानदण्ड और वास्तविक

कीमत को ध्यान में रखा जाएगा । इस कच्चे माल की खपत जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के उत्पादन के लिए की जाती है ।

69. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध माल की निवल बिक्री वसूली जांच अवधि के दौरान एन आई पी से कम रही । इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध माल की कम बिक्री नहीं की गई है ।

70. प्राधिकारी घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई इस जानकारी के आधार पर आगे यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान कोई कीमत कटौती तथा कीमत-प्रतिबंध नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध देशों से संबद्ध माल का कोई आयात नहीं हुआ है । उपरोक्त को देखते हुए यह समापन किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों के कारण जांच-अवधि के दौरान कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है । घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से तथा लाभप्रदता में गिरावट संबद्ध माल के अन्य घरेलू उत्पादक से आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुई होगी । इसलिए यह सुझाव देने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रतीत नहीं होता कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने से क्षति एवं पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

71. निर्णायक समीक्षा के मामले में पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क (5) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को ऐसी राय बनानी है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है । मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्री ने यह दावा किया है कि संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग के लिए कीमत 1695 रु० प्रति एमटी से 3375 रु० प्रति एमटी के बीच तुरन्त घटाने पर बाध्य होना पड़ेगा । यह भी दावा किया कि पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से संबद्ध माल की लैण्डेड कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत कम हो जाएगी । इसके फलस्वरूप, कीमत मंदी, कीमत प्रतिबंध, यथोचित लाभ में संभाव्य हानि होगी जो संबद्ध देशों से पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के औचित्य के लिए पर्याप्त होंगे ।

72. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान डिमिनिमस पाटन मार्जिन तथा डिमिनिमस मात्रा के उपबंधों की ओर भी आकृष्ट किया है और इंगित किया है कि ये नियम 23(3) के तहत निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होते हैं । उन्होंने प्राधिकारी का ध्यान आईबीबी के मामले में माननीय सीगैट द्वारा दिये गए फैसले की ओर भी आकृष्ट किया जिसमें आदेश में कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए वे यह निष्कर्ष रिकार्ड कर दें कि भारत में पाटित वस्तुओं के आयात से भारत में स्थापित उद्योगों को वास्तविक क्षति

करते या आशंका है। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जांच करने हेतु बाध्य हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से आईबीबी के आयात से भारत में किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति होने की आशंका होगी, यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए। सीगैट द्वारा यह भी निर्णय दिया गया कि चीन से आयातित आईबीबी पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच-अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हो सकती है। यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाए तो भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

73. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान कोरिया से यूएस ड्राम्स के मामले में डिमिनिमस अथवा किसी आयात नहीं होने के मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय की ओर भी आकृष्ट किया। पैनल ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के मूलपाठ की जांच की और कोरिया के इस दावे को रद्द किया कि अनुच्छेद 11.2 में पाटनरोधी शुल्क का तब तत्काल प्रतिसहरण किए जाने की आवश्यकता है जैसे ही आयातक को पाटन समाप्त करता हुआ पाया जाए और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने पर किसी ऐसी परिस्थिति में पहले रोक लगा दी जाए। इसमें वह स्थिति शामिल नहीं जहां पाटन जारी है। पैनल ने आगे यह भी नोट किया कि अनुच्छेद 11.3 के निर्णायक उपबंध में यह निर्धारित करने की परिकल्पना है कि क्या किसी पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होगी।

74. प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि इस जांच में मैसर्स पीटी पोलीप्राइमा, इण्डोनेशिया के सिवाय किसी भी निर्यातक में सहभागिता नहीं की है। किन्तु, सहयोग करने वाले मैसर्स पी टी पोलीप्राइमा, इण्डोनेशिया ने जांच अवधि तथा पिछले वर्षों के दौरान संबद्ध माल का निर्यात नहीं किया और उन्होंने विगत जांचों में भी सहभागिता नहीं की है। डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता द्वारा घरेलू उद्योग तथा आयातक को उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों के आधार पर टिप्पणी करते हैं कि संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध माल का आयात वर्ष 1999-00 के दौरान हुए 63648 एमटी से घटकर जांच अवधि में शून्य हो गया। संबद्ध देशों से आयात भी जो 1999-00 में 2021 एमटी के थे, जांच अवधि में घटकर शून्य हो गए। आयातक द्वारा दावा किया गया कि पिछली अवधियों के दौरान जो अधिक आयात किए गए वे सब अग्रिम लाइसेंस पर किए गए थे। प्राधिकारी को यह नोट करना महत्वपूर्ण लगता है कि संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से हुए आयात जांच-अवधि के दौरान घटकर शून्य रह गए।

75. अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निवेदन में यह गुणावगुण नहीं होते हैं कि संबद्ध माल की उनकी निवल बिक्री कीमत उस पाटनरोधी शुल्क के बराबर कम हो जाएगी जिसे मूल तथा समीक्षा जांच के दौरान लगाया गया था बशर्ते प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को वर्तमान निर्णायक समीक्षा में रद्द कर दें। प्राधिकारी टिप्पणी करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भी संबद्ध माल का कोई आयात नहीं हुआ। प्राधिकारी आगे यही नोट करते हैं कि संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात में सीमाशुल्क में कटौती के बावजूद गिरावट आई है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध माल की मांग में जांच अवधि के दौरान विगत वर्षों की तुलना में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अतः, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि पाटनरोधी उपायों के अभाव में संबद्ध देशों से आयातों की पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति होगी। अतः प्राधिकारी यह यथोचित समापन नहीं कर सकते कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण संबद्ध देशों से आयात घटकर शून्य हो जाएंगे जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू वाले देशों से आयात भी इसी प्रकार घटकर शून्य रह गए हैं।

76. सीगैट द्वारा की गई टिप्पणियों की तरह प्राधिकारी ने इस तथ्य का और आगे विश्लेषण किया कि पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने अथवा समाप्त कर देने के फलस्वरूप क्या घरेलू उद्योग को पुनरावृत्ति की दृष्टि से कोई आशंका है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-ii के उप नियम vii में यह व्यवस्था है कि वास्तविक क्षति की आशंका का आधार तथ्य होंगे और मात्र दोषारोपण, निराधार कल्पना अथवा अप्रत्यक्ष संभावना नहीं। परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन जिससे ऐसी स्थितियां बने जिसमें पाटन के कारण क्षति हो, का स्पष्टरूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और वह सन्निकट हो। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में भारी निर्यात योग्य बेशी माल जमा है जो स्पष्टरूप से यह इंगित करेगा कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त कर देने की स्थिति में वह माल भारत की ओर आने लगेगा। किन्तु, अन्य कारकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की किसी आशंका का दावा नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी यह समापन करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पाटनरोधी उपायों के अभाव में पाटित कीमतों पर भारत को निर्यातों की पुनरावृत्ति की संभावना व्यक्त नहीं होती है।

77. उपर्युक्त आर्थिक संकेतकों का अर्थ यह है कि संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति जारी अथवा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसलिए, प्राधिकारी संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की सिफारिश करते हैं।
78. नबंदरगाह पर उतारते समय मूल्य: जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध माल के कोई आयात नहीं होने की स्थिति में प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध माल के लेण्डेड मूल्य का निर्धारण नहीं कर सके।

डी. निष्कर्ष:

पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि

- (i) इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड तथा कोरिया गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुद्ध टैरेफथैलिक एसिड(पीटीए) का जांच-अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया गया है।
- (ii) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयात से वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- (iii) विभिन्न आर्थिक संकेतकों और क्षति-मानदण्डों से यह परिणाम निकलता है कि संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने से पाटन तथा क्षति जारी अथवा उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसलिए, प्राधिकारी इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड तथा दक्षिण कोरिया से भारत को निर्यातित शुद्ध टैरेफथैलिक एसिड (पीटीए) पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की सिफारिश करते हैं।
- (iv) इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2003

FINAL FINDINGS

Subject :—Anti-Dumping Investigations concerning Sunset Review of Anti-Dumping Duty on Imports of Pure Terephthalic Acid (PTA) from Indonesia, Korea (RP) and Thailand.

No. 14/9/2002-DGAD.— Having regard to the Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury), Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

The procedure described below has been followed:

- (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules as per Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 initiated Sunset Review to review the need for continued imposition of anti-dumping duty on imports of PTA (Pure Terephthalic Acid) as indicated in the original preliminary findings of the Authority dated 4th September 1997 and the Customs Notification No.85/97 dated 21st November 1997, Final Findings No. 14/1/1996-DGAD dated 19th March 1998 and customs notification No.13/98 dated 28th April, 1998 originating in or exported from Thailand, Indonesia and Korea (RP) (hereinafter referred to as subject countries). A new Shipper review was also initiated on 13th Oct 98 and 12th November 98 for the subject goods originating in or exported from Siam Mitsui PTA Co Ltd and PT Amoco Mitsui PTA Indonesia respectively vide No 7/2/98-DGAD and the final findings were notified on 16th June 1999. The findings of mid term review were notified vide notification no 26/1/98-DGAD dated 29/5/2000 recommending imposition of Anti Dumping Duty on imports of PTA from Korea (RP).
- (ii) The Authority notified the initiation of this Sunset review vide Public Notice dated 22nd May 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigations

- concerning imports of the Pure Terephthalic Acid classified under Chapter 29 under Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 originating in or exported from subject countries.
- (iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were available in view of investigations conducted earlier) and industry/user associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2).
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were available in view of investigations conducted earlier) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
 - (v) The Embassy of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the known exporter were also sent to the Embassy of the subject countries in New Delhi in accordance with Rule 6(3). Response was received from M/s. PT Polyprima Karyareksa, Indonesia.
 - (vi) Request was made to the Central Board of Excise & Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
 - (vii) The Authority provided a copy of the initiation notification to the known exporters and the Embassies of the subject countries in New Delhi in accordance with Rules 6(3) supra.
 - (viii) The Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4);
 - (ix) A questionnaire was sent to the known importers/user associations of the subject goods whose details were made available by the petitioner for necessary information in accordance with Rule 6(4). Response / information to the questionnaire was filed by the importer M/s. Indo-Rama Synthetics Ltd. New Delhi.
 - (x) Information regarding injury was sought from M/s. Reliance Industries Ltd. (RIL), M/s. MCC PTA India Corporation Private Limited and M/s. Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd., Mumbai. The total cost of production / injury information was furnished by M/s. RIL. M/s. Bombay Dyeing submitted some costing information regarding the product DMT.
 - (xi) Cost investigation of M/s. RIL, Mumbai was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally

- Accepted Accounting Principles (GAPP) and the information furnished by the Petitioner.
- (xii) An opportunity was provided to all interested parties to present their views orally on 23rd October 2002. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
 - (xiii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7);
 - (xiv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 9th April 2003.
 - (xv) **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rule.
 - (xvi) The period of investigation (POI) considered is from 1st April 2001 to 31st December 2001.

B. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY, EXPORTERS, IMPORTERS, USER ASSOCIATIONS AND OTHER INTERESTED PARTIES & EXAMINATION BY THE AUTHORITY

2. The views expressed by various interested parties have been discussed in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

Initiation of Sunset Review

3. The Designated Authority initiated the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Pure Terephthalic Acid (herein after referred to as PTA) originating in or exported from Indonesia, Korea (RP) and Thailand pursuant to the final findings notification No. 14/1/96 dated 19/3/98 and subsequent review notification No. 26/1/98-DGAD dated 29/5/2000. This sunset review was initiated vide notification no. 14/9/2002-DGAD dated 22/5/2002.

C PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product considered in this investigation is Purified Terephthalic Acid (popularly known as PTA and referred to PTA hereinafter in this investigation).
5. PTA is classified under customs Sub heading 2917.36 of the Customs Tariff Act 1975 and further classified under ITC 29173600. PTA is a white free flowing powder free from any visual contamination and is used in the manufacture of Polyester Staple Fibre (PSF), Polyester filament Yarn (PFY), Polyester Terythialate (PET), bottle grade resins and Polyester Filament Yarn film.
6. The substitute for PTA is Di-Methyl Terephthalate (DMT). There are no arguments on the product under consideration. The detailed technical description of these catalysts is indicated in the original investigation and the related Custom Notifications. Since the present investigation is only a review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995, the Authority holds that the scope of product under consideration is limited to the original investigation as indicated above.
7. Rule 2(d) relating to the definition of like article specifies that like article means an article which is identical or alike in all respects to the articles under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation. From the first part of the definition of the like article, it is clear that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation only in the absence of article "identical or alike in all respects". Therefore, the usage of the term "in the absence of " is of critical significance for interpretation of the term like article under the statute. There is no dispute that the words " in the absence of " have to be understood in the context of domestic industry alone whether there exists a domestic industry producing the like article or not. In other words, if there is no domestic industry producing identical article, the law permits the Authorities to cover in the scope of the term even those articles, which have closely resembling characteristics. The Authority recalls that during the main investigations DMT was taken as a like article in the context of antidumping investigations in the absence of any domestic industry producing an article identical to PTA. In the instant sunset review, the Authority notes that there is a domestic industry namely, M/s. RIL producing an article identical to PTA, therefore, the Authority considers PTA produced by the domestic industry as like article to the PTA imported from the subject countries in this investigation. There are no arguments under the Like article from any of the interested parties.

INITIATION, REVIEW, STANDING AND DOMESTIC INDUSTRY.

Views of Importer M/s. Indo-Rama Synthetics (I) Ltd (IRSL), New Delhi.

8. Indo Rama Synthetics (I) Ltd. (IRSL) wishes to submit that, this PTA Sunset Review case is an extraordinary case. The original case was initiated based on a complaint made by M/s. Bombay Dying & Manufacturing Company Limited (BDML) alleging dumping of PTA but claiming injury on DMT an alleged like product. In the original investigation, the dumping values were determined on the basis of the product PTA whereas the injury analysis was completely based on the domestic industry consisting of the DMT (a roped in like product). Thus, the causal link established was vague and weak with respect of PTA. Noticeably, the oligopolistic producer of PTA in the country M/s. Reliance Industries Limited (RIL) was excluded from the definition of the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules 1995, being importer of PTA. However, RIL continued to be the concerned party and absolute beneficiary of the protection granted under the proceedings. The exit and entry of RIL from the definition of domestic industry in the present case has been conspicuous and obviously on the basis of their convenience and not strictly as per the provisions of Law in force.
9. IRSL proceeded with a note of protest on considering M/s RIL as the domestic industry in the sunset review case though they had been expressly excluded as such in the original proceedings. In view of the special circumstances of the original case IRSL considers that in a sunset review the domestic industry definition cannot be completely altered by considering a company, which was expressly excluded from the domestic industry definition and now to exclude all others who constituted domestic industry.
10. IRSL wishes to submit that the initiation of the case under Section 9A(5) of Custom Tariff Act 1995 under Rule 5(1) has been clearly contrary to the express provision of Section 9A(5) and Rule 5(1) supra and is also in violation of the Article 11.4 of ADA 1995, Article 5.8 of ADA 1995, Article 3.2 of ADA and Article 3.7 of the ADA as detailed hereunder.
11. The instant sunset review case is initiated under the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act 1995 which reads as follows:
 - a. The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect

on the expiry of five years from the date of such imposition:

- b. Provided that If the Central Government, in a view, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;
 - c. Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.
12. Corresponding provision of ADA 1995 are set out in Article 11.3, which reads as follows: "Notwithstanding the provisions of paragraph 1 & 2, any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiated or upon a duty substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The duty may remain in force pending the outcome of such a review.
13. It would be clear from a plain reading of the Section 9A(5) and Article 11.3 supra that prior to the initiation of the case under Section 9A(5), the Central Government has to have an opinion while Article 11.3 lays down the condition of the authorities to determine that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Both the Customs Act 1995 and ADA 1995 places specific duty on the Authorities to arrive at a opinion/determination on the basis of the adequacy and accuracy of the information and evidences prior to the initiation of the case.

Submissions made by the IRSI after the Disclosure statement:

14. On the issue of initiation, standing of the domestic industry and like products IRSI wishes to reiterate its submissions made earlier in this respect with further observations that DGAD can not over look the

provisions of Rule 5(4) which spells out specific procedure to be followed when the investigation is initiated suo-moto.

Views of the M/s. Bombay Dyeing & Mfg. Co. Limited, Mumbai

15. The domestic industry has been immensely benefited in the last four and half years from the imposition of the anti dumping duty. There have been no imports of PTA during the 1st April 2001 to 31st December 2001. We firmly believe that due to the imposition of anti dumping duties, the imports from the subject countries stopped completely. This happened due to the fact that imports from the subject countries are not competitive at fair and non-dumped prices. Therefore, removal of the duties would certainly allowed exporters to resume their exports to India at dumped prices causing injury to the domestic industry. We, therefore, request that anti dumping should continue. It may be noticed that in spite of the anti dumping duty, we had incurred losses for the investigation period.

Views of the Domestic Industry - Reliance Industries Limited (RIL)

16. It has been vehemently argued by IRSI that the scope of the domestic industry cannot change from the original investigation. It has further been stated that since RIL was specifically excluded from the scope of the domestic industry in the original investigation, the Designated Authority is not at liberty to consider RIL as part of the domestic industry. Under Rule 2(b), the term 'Domestic Industry' has been defined as under:

'Domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case (such producers may be deemed) not to form part of domestic industry.

17. It may be recalled that the definition of domestic industry was amended vide Customs Notification No.44/99-Cus(NT) dated 31st May 1999 wherein the word 'shall' was replaced with the word 'may'. It has been brought out by the Hon'ble Designated Authority in its final findings dated 19th March 1998 that RIL stands excluded from the purview of the domestic industry, as it was an importer during the period of investigation. It is important to note that at the relevant time, the law did not give any discretion to the Designated Authority with regard to inclusion or exclusion of any importer from the scope of the domestic industry irrespective of the reasons for which the imports had been made.

18. In the present sunset review, the Designated Authority is required to examine the test prescribed under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act for the domestic industry as it exists at the time of such review. There is no indication in the law directly or indirectly, that the injury analysis is required to be restricted only to the domestic industry who had filed the petition for the original investigation. IRSL has not pointed out any provision of law under which the Designated Authority is restricted to carry out the Sunset Review investigation only in the context of the original complainant. Apart from this legal position, the entire jurisprudence of WTO panel decisions suggest that the injury analysis even in a fresh investigation should be done for a substantial portion of the domestic industry and not restricted to only the complainants.
19. An issue has been raised by IRSL whether the Sunset Review initiated under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act has been initiated on the basis of a complaint made by domestic industry under Rule 5(1) or suo moto under Rule 5(4) of the Anti-dumping Rules. We are shocked to see the averments made by IRSL imputing statements to the office of the Designated Authority which were never made. It appears that IRSL is surreptitiously trying to create facts for ulterior motives. We request the Hon'ble Designated Authority to take serious note of such submissions.
20. As regards the legality of the argument made by IRSL, we draw the kind attention of the Hon'ble Designated Authority to the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act which casts a responsibility upon the Hon'ble Designated Authority to review the need for continuation of anti dumping duties if the conditions mentioned therein are met with. In fact, duties would cease to exist after a lapse of five years if the Designated Authority (D.A.) does not initiate an action to extend it further under the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act. Since the responsibility rests entirely with the D.A., there is no provision made under Section 9A(5) for the domestic industry to request for the initiation of a Sunset Review. In fact, the representative of the IRSL has attempted to read the provisions of Rule 5 into Section 9A(5) of the Customs Tariff Act whereas no such linkage is envisaged under the present scheme of the Act and the Rules. It is our respectful submission that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the plain language used, which means that attention should be paid to what has been said as also to what has not been said. Had the intention been to initiate a Sunset Review only at the instance of the domestic industry, then the legislature would have categorically made the provisions of Rule 5 applicable to a review case under Section 9A(5) also. Thus, it is abundantly clear that Section 9A(5) is a self-contained provision with regard to 'Sunset

Reviews' or 'Expiry Reviews' and there is no linkage with Rule 5(1) or Rule 5(4) as being sought to be made out by IRSL.

21. As aforesaid, the rights and obligations of Sunset Review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act vests only in the DA as is evident from the language employed by the Legislature. It is the discretion of the Designated Authority whether or not to review the need for continuation of anti-dumping duties.
22. In the instant case, it may be recalled that the DGAD vide its letter dated 27th March 2002, sought comments from RIL regarding the need for continuation of anti dumping duties and the requirement of review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975. RIL vide its letter dated 17th April 2002, informed the Designated Authority about its interest in proforma in which information is to be supplied by the domestic industry to assist the DA to arrive at appropriate findings under Section 9A(5), of the Customs Tariff Act. Thereafter, the DA in exercise of its powers under Section 9A(5), initiated review under notification dated 22nd May 2002. RIL as a part of the domestic industry submitted information to the DA as called for in para 6 of the initiation notification dated 22nd May 2002, to enable the DA to examine the need for continuation of duties. It appears that IRSL has completely misguided itself in presuming that the letter of interest by RIL in response to an inquiry by the Designated Authority or information supplied in response to initiation notification can be considered as a complaint. In fact, the absurdity of the presumption is writ large from the fact that the so-called complaint is subsequent to initiation of sunset review. Even the letter dated 17th April 2002 is merely seeking clarification from the office of the DA about the proforma in which information is to be provided and expressing interest that the DA should exercise powers to review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act. It is also interesting to note that IRSL in its written submissions (para 2.09 & 2.10) dated 1st November 2002 have themselves stated that there has been no formal complaint by the domestic industry in stark contradiction to the averments made in the earlier paragraphs of the said written submissions. In the aforementioned premises, the reference of IRSL to the present initiation as 'illegal' is itself, ironically, wholly devoid of legal basis and factual substance.

Examination by Authority

23. It is confirmed by the Authority that it has initiated sunset review in exercise of the powers vested under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act 1975 as amended on 22nd May 2002. The Authority recalls that under the rule 4 (i)(e) of the Anti Dumping Rules, It shall be the duty of the Designated Authority to review the need for continuance of the Anti Dumping duty.

24. As regards the observations made by some interested parties that the requirements of the review are required to be fulfilled with respect to Article 5 of the Agreements of the Anti Dumping, the Authority recalls that under the Rule 23 (3) of the Anti Dumping rules made under the provisions of the Customs Tariff Act 1975 as amended, the provisions of the rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of the review. This provision does not include Rule 5(1) so, it can be concluded that there can not be a linkage between the Rule 5(1) and Rule 23 in so far as review is concerned. Moreover, it is noted that Section 9A(5) is a self-contained provision with regard to 'Sunset Reviews' or 'Expiry Reviews' and there is no linkage with Rule 5(1) or Rule 5(4) as being sought to be made out by IRSL. As per 11.3 of the Anti Dumping Agreements, "Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury
25. Hence as per the above provisions it is seen that the main observation of the Authority in the sunset review is to examine on their own initiative that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority in this case had called for certain information in its letter dated 27th March 2002 from the RIL (which was taken as the domestic industry during the earlier mid term review). RIL vide its letter dated 17th April 2002, informed the DA about its interest in the continuation of anti-dumping duties and also enquired about the proforma in which information is to be supplied by the domestic industry to assist the DA to arrive at appropriate findings under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act. Thereafter, the DA in exercise of its powers under Section 9A(5) has initiated review under notification dated 22nd May 2002.
26. As regards the standing issue, it is observed that the Authority has in exercise of its powers under Section 9A(5) has initiated review. M/s Reliance Industries Ltd (RIL) though excluded from the scope of the domestic industry in the main investigation was considered as the interested party in this case with reference to rule 2© of the Anti Dumping rules. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, the Domestic Industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any". Here the Authority proposes to take PTA manufactured by the Reliance Industries Ltd as the like article to the PTA imported into India from the subject countries. The Authority further notes that M/s RIL has not made any imports

during the POI in this review and it is also observed that M/s RIL is the largest (having more than 50% of the domestic production) producer of the PTA, the subject goods, and has been taken as the domestic industry in the mid term review earlier by the Authority. The Authority, therefore, treats M/s RIL as the domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) of the Anti Dumping rules in this sunset review.

Dumping:

Views of Importer M/s IRSL

27. Without prejudice to the argument of illegal initiation of the sunset review, IRSL now wishes to deal with merits and maintainability of this case and submits that as per the questionnaire response of RIL filed on 18th July 2002 itself, there are two admissions:

(i) that there has been no import of the product concerned during the investigation period from the countries against whom the case has been initiated i.e. Korea, Thailand and Indonesia; and

(II) Further, RIL has also admitted that during the investigation period that the product concerned has not been imported from any other country also. RIL also confirmed that whatever imports that took place even before the investigation period were under Advance License, not posing any commercial competition to domestic producers.

28. Since there are no imports at all during the investigation period as per RIL admission itself, there is no continuance of any dumping, causing injury during the investigating period selected by DGAD at the behest of so-called petitioner. The imports of the product under investigation from the countries is nil which is di-minimus under provision of rule 14(d).
29. These being the facts case the investigation deserves to be terminated forthwith as prescribed by the rules 14 (d) of the rules 1995.
30. IRSL also wishes to submit that in the case of Low Carbon Ferro Chrome (LCFC) case No.44/1/99-DGAD, the Designated Authority had itself determined that in absence of any imports during the investigation period neither there is a continuance nor there is threat of recurrence of dumping and, therefore, the case could not be maintained.
31. The whole case has been initiated on the basis of presumption, presuppositions and wishful thinking without any information or evidence capable of being examined for adequacy and accuracy at the time of initiation of the case mainly on the following factors:

- (i) That there will be significant import that will take place from the subject countries (no evidence submitted).
- (ii) That the prices of such imports from the subject countries will necessarily be the dumped prices (no evidence submitted).
- (iii) That the imports that will take place from the subject countries will have a causal effect on the domestic industry, which will necessarily, suffer injury due to such imports (no evidence submitted).
- (iv) That either no imports will take place from other countries or if they take place, they will be at non-dumped prices, or insignificant to have any negative impact on the domestic industry (no evidence submitted).

Views of Domestic Industry – M/s. RIL.

- 32. Though we do not have the exact cost details of these producers who are dumping the product, as these would be trade secrets and not disclosed. Based on the global PTA manufacturing cost analysis carried out by M/s. DeWitt & Co. (USA), the normal value of PTA is calculated for the POI. Though the cost studies carried out by DeWitt & Co. is in 1997, there are no changes in cost except for the cost of two principal raw materials i.e. Paraxylene and Acetic Acid.
- 33. RIL has obtained the statistics from Ports with regard to the imports of PTA. It is interesting to note that there have been no imports of PTA from the subject countries during the period of investigation in the domestic market. There have been some imports against advance licenses which are not relevant for the purpose of this review investigation in view of the fact that PTA imported against advance licenses is not subject to anti dumping duties as they do not enter the commerce of the country.
- 34. It may please be seen that under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, the maximum period for which anti dumping duties can be levied is restricted to five years. However, in terms of proviso to this sub section (5), the DA may extend from time to time the period of such imposition for a further period of five years provided it is of the opinion in a review that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this section, we are providing information with regard to the massive exportable surpluses in the subject countries, which would clearly indicate that the same would find their way into India if the anti dumping duties are removed.
- 35. We would also like to state here that the fact that there have been

no imports of PTA during the course of the period of investigation from the subject countries is itself indicative of the uncompetitive nature of the prices of these countries. The cessation of the anti dumping duties on imports from the subject countries would certainly result into recurrence of dumping. It is respectfully submitted that the fact that there have been no imports during the period of investigation is of no consequence in as much as the only test required to be examined by the DA is the 'test of recurrence', which in the instant case is adequately satisfied.

Views of Exporter - M/s. PT Polyprima Karyareksa

36. We make this submission on behalf of PT Polyprima Karyareksa following the public hearing at Udyog Bhavan on 23rd October 2002.
37. Section 9A of the Customs Tariff Act ("the Act") which has its origin in Article 11 of the WTO Anti-dumping Agreement ("the Agreement"), provides that antidumping duty shall cease to have effect on the expiry of five years from imposition unless the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to a recurrence of dumping and injury.
38. It is not possible that the Central Government could reach an opinion in this review that the cessation of antidumping duty in relation to imports of PTA from Indonesia is likely to lead to a recurrence of dumping and injury. There have been no imports of PTA from Indonesia since 1999 and there is no positive information available to the Central Government, which demonstrates that there is even a likelihood that imports from Indonesia will recur, let alone the likelihood that there will be a recurrence of imports from Indonesia at dumped prices in the absence of antidumping duty. There is no reasonable basis upon which the Central Government can be satisfied that recurrence of dumped imports from Indonesia is likely in the absence of anti dumping duty. That there may be recurrence of imports of the goods concerned from Indonesia is mere conjecture and has no factual basis.
39. In its written submission to this review and in its oral Presentation to the public hearing, domestic producer Reliance Industries Ltd. has asserted that cessation of anti dumping duty is likely to lead to a recurrence of dumping but has provided no information of any change in circumstances which would reasonably lead to the Central Government forming an opinion that a recurrence of dumping from Indonesia is likely. The language of the Act and the Agreement make it very clear that there must be a demonstrated probability that cessation of antidumping duty will lead to recurrence of dumping. It is not enough that there is a remote possibility that dumping will recur in the absence of anti-dumping duty.

40. Reliance Industries Ltd. asserts that the fact that there have been no imports during the period of investigation is of no consequence and that the "test of recurrence" is inadequately satisfied. It is of note that in the two years immediately following the imposition of the antidumping duty imports from Indonesia continued but in the past three years there have been no imports from Indonesia. It is, therefore, cannot be assumed that it is the antidumping duty which has caused the cessation of imports from Indonesia.
41. It is also of significant note that the complainant in the original investigation, which brought the imposition of the anti dumping duty, M/s. Bombay Dyeing, has made no submission to this review and appeared to have attended the public hearing at the behest of another party.
42. In summary, there is no evidence available to the Central Government which could reasonably lead to an opinion that cessation of anti dumping duty on imports of the goods concerned from Indonesia is likely to lead recurrence of imports of those goods from Indonesia at dumping prices. That there will even be recurrence of imports per se from Indonesia is mere conjecture.

Comments by M/s PT Polyprima Karyareksa to the disclosure statement

43. The domestic industry has failed to provide the Designated Authority with anything of substance in support of its claim that in the absence of anti-dumping measures there will be a recurrence of imports from Indonesia at dumped prices. It asserts that "the cessation of anti-dumping duties from the subject countries would certainly result in recurrence of dumping" but provides nothing but rhetoric to support its assertion. The domestic industry's case concerning the recurrence of dumping seems to rely on its assertion that there are massive exportable surpluses in the subject countries and there have been no exports to India during the period of investigation. This surely does not demonstrate the likelihood of the recurrence of exports to India at dumped prices in the absence of anti-dumping measures. We share the Authority's view that a recurrence of dumping on account of cessation of anti-dumping duty is not conclusive. We believe that this view must lead to a conclusion that Designated Authority cannot be satisfied that the cessation of anti-dumping duty is likely to lead to a recurrence of dumping.

Examination by Authority

Dumping

44. The Authority sent the exporter's questionnaire to the known

exporters of PTA for the purpose of determination normal value in accordance with 9A(1)C. However, none of the exporters mentioned in the main investigation responded to the Authority. The Authority, therefore, holds that the exporters from the subject countries have not cooperated with the Authority as envisaged under the Rules. The Authority also holds that the primary responsibility to establish normal value of PTA rests with the exporters/producers who have failed to cooperate with the Authority.

45. The Authority also sent the importers' questionnaire to the known importers of PTA. Only one of the importers viz. M/s. Indo Rama Synthetics limited, have responded to the Authority.
46. As regards the export price, the Authority notes that none of the exporters/importers have furnished any export data of the subject goods from subject countries. The authority notes the contention of the domestic industry that there have been no imports of PTA from the subject countries during the POI in the domestic market. The domestic industry has also added that there have been some imports against advance licences which are not relevant for the purpose of this review investigation in view of the fact that PTA imported against advance licences is not subject to anti dumping duties as they do not enter the commerce of the country.
47. For the present investigation, a request was made to DGCI&S Calcutta to furnish details of imports of the subject goods originating in or exported from subject countries during the POI. DGCI&S have now also confirmed that there is no import trade of the PTA during the POI from the subject countries.
48. After examining the statistics furnished by the DGCI&S and claim of the industry, the authority concludes that no exports has taken place of the subject goods from the subject countries to India during the POI. In the absence of exports from the subject countries, the Authority does not propose to estimate the average export price of the subject goods from the subject countries to India during the POI.
49. The Authority, therefore, holds the view that under such a situation, a recurrence of dumping on account of cessation of anti dumping duty is not conclusive and therefore, does not consider it appropriate to evaluate the normal value with respect to the subject goods from subject countries. The Authority is of the view that as there are no exports of subject goods from the subject countries in India during the POI, there is no dumping of subject goods and in view of the absence of export price of the subject goods to India during the POI, the Authority is unable to determine the dumping margin in pursuance of the principle laid down in Para 6 of the Annexure I to the Rules.

INJURYSubmissions made by the Domestic Industry

50. As indicated, the test that is required to be applied by the DA in a sunset review case is to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act. Therefore, the parameters and the tests applicable for assessment of material injury cannot be applied in the case of sunset review. In this connection, attention of the DA is also invited to the ruling of the Hon'ble CEGAT in the case of IBB from China PR (citation 2001 (127) ELT 629 (Tri-Del). However, since there is no separate proforma prescribed by the DA for a sunset review case, we are providing the requisite information in proforma IVA. Notwithstanding, our basic submission that the Application Proforma for new cases is not appropriate for a sunset review case, we would indeed like to bring to the attention of the DA that the domestic industry has benefited by the imposition of anti dumping duties on imports from the subject countries.
51. The domestic industry during the period of investigation has sold PTA at an average price of Rs. **** per MT. The domestic industry has been able to sustain the existing price level primarily on account of the existence of anti dumping duties. The performance of the domestic industry can be seen from the various economic and financial parameters as indicated.
52. While the annualized production has marginal declined during the period of investigation over 2000-01 from ****/ MT to ****/ MT, the domestic industry has still been operating at a high capacity utilization level of ****%. As regards the quantum of sales, there has been an appreciable increase even though the sales have declined in value terms. The domestic industry has also been able to earn some profits on its sales even though the net sales realization has been low resulting in a lower level of profitability.

Import of PTA from Indonesia, Thailand And Korea		
	Qty (MT)	CIF \$/MT
99-00	2021	422
00-01	3955	456
2001-02	NIL	NIL

53. As a result of present review, in the unlikely event that

the anti dumping duties are withdrawn, the prices of imported PTA from the subject countries would be landing at prices lower to the extent of the incidence of anti dumping duties. As a result, the Indian industry would also be required to bring down the prices to the same extent, which would wipe out the entire profit of the industry. This would take the domestic industry to a situation, which existed prior to the imposition of anti dumping duties.

- 54 The expected fair price during POI for RIL with a reasonable return on its investment works out to Rs.****/MT. The withdrawal of anti dumping duties will certainly result in price depression, price suppression and eventual loss or severe loss of reasonable profit, which are more than sufficient to justify the continuation of anti dumping duties on the imports of PTA from the subject countries.

Injury Information to the Domestic Industry			
Parameters/Years	99-00	00-01	POI (A)
Installed capacity Index	100	100	100
Production Index	100	101	99
Capacity Utilisation Index	100	101	99
Sales Indigenous Index	100	86.15	90.86
Exports sales Index	100	296.32	184.43
Captive consumption Index	100	98.57	73.81
Opening stocks Index	100	79.12	76.6242
Closing stocks Index	100	96.85	100.883
Profit Index	100	101.73 91	81.0172
Employment Index	100	100	100
Market Share Index	85%	79%	73%

Submissions made by the Domestic Industry after Disclosure

55. In connection with, we would like to submit that we have given sufficient data and cogent reasoning to substantiate our case of extension of anti-dumping duties on imports of PTA for another five years. In this regard, we had also furnished the jurisprudence as has developed in European Union and the USA. It clearly emerges that the fact no imports have taken place from the subject countries in the immediately preceding period can never be a basis of arriving at a conclusion that there is no case for extending the duties. We would humbly request the Hon'ble Designated Authority to kindly take all the submissions made by us at the time of the public hearing and also the additional submissions dated 17th January 2003 before a final decision is taken.

Submissions made by the Importer M/s Indo Rama Synthetics (I)Ltd

56. IRSL wishes to submit that the instrument of Anti Dumping Duty is not prescribed for providing protection per se unless there are positive evidence of significant imports taking place, or likely to take place at the dumped prices causing injury to the domestic industry. This instrument cannot be invoked on mere surmises, conjectures, presuppositions and allegations not supported by positive evidences.
57. It is submitted that there are no positive evidences provided by RIL, which lead to any remote reference on recurrence of dumping or injury. The possible positive evidence could have been order, LC, quotations, invoices for import from the alleged countries or even enquiry. In absence of all these positive evidences the pre-supposition of recurrence is only wishful and presumptions.
58. If PTA has to be considered separately as independent Product which supposedly is in the present sunset review case as announced by DGAD during hearing, then capacity which stood **** Lac MT at the time of the initiation of the case has risen to **** Lac MT which shows increase of ****% in installation capacity. The production has shot up from **** lac MT to **** lact MT, a phenomenon growth of ****%. Capacity utilization for the same period has gone up from ****% to ****%, a growth of ****%. In fact, production of PTA has reported to be even higher than the installed capacity.
59. On the price front during the period of imposition of anti Dumping duties i.e. from April 1998 to October 2002 the prices of PTA per kg have shot up from Rs. **** per kg. To Rs. **** per kg, an increase of ****%, as compared to protection granted between ****% to ****%. Even increase in prices during investigation period (average price during investigation periods is Rs. **** per Kg.) are ****% higher than the prices when anti dumping duty was imposed. This price comparison is based on RIL's own prices lists available on website. All these positive evidences are there pointing towards substantial growth and strength of the domestic industry whereby wishful threat of recurrence is nothing more than a day dream without an iota of evidence and therefore on this account the case deserves to be terminated.
60. Views of M/s IRSL after Disclosure statement: There is neither any dumping during POI nor there are any chances of recurrence of dumping in future. There is neither any injury established during POI nor there are any foreseen chances of recurrence of injury or any other established factors as per

Annexure II generally and sub-rule VII of Annexure II of Anti-dumping Rules. The only unsubstantiated submission made by Domestic Industry is allegation of massive exportable surplus without any proofs of facts, of its possibility of exports to India like enquiries, purchase orders, expression of interests, confirmed orders, LC's and allied documents. There is merely an allegation, conjecture and refers to an extremely remote possibility. The fact is that there have been no exports of PTA to India during POI even from non-target countries despite reduction in custom duties and Nil Anti-Dumping Duties. In the light of above, IRSL, while reiterating the submissions already made earlier, submits that the examination leads to a conclusion of no material threat or recurrence of injury.

Views of M/s MCC PTA India Corp. Private Ltd :

61. The price trend of the PTA is already moving downwards from August 2002 in the international market as well as in the domestic market. 4 million tones of extra PTA would become available in the international market in the next year due to the commissioning of new plants and also due to the capacity expansion of the new plants. This poses a material threat of injury to the Indian PTA producers. Thus revocation of the anti Dumping duties would result in the dumping and recurrence of serious injury.

Views of M/s MCC PTA India Corp. Private Ltd after Disclosure

62. With the recent addition of capacities, supply of PTA has outgrown the corresponding demand in the international market. The market imbalance has further been aggravated by the drastic reduction of operation since March 2003 by the Chinese polyester manufacturers, the main importing market of PTA which absorbed more than 4 million tons of imported PTA in the year 2002. Consequent to such reduction of PTA demand in China, a huge quantum of PTA is floating in the Asian market and the threats of dumping looms large in the domestic market.

Examination by the Authority:

63. The Authority notes that as per Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 " the anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provides further that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year”.

Also under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.

Since under the present investigation it is to be evaluated as to whether cessation of anti dumping duties would lead to continuance or recurrence of dumping and injury, the Authority has considered appropriate injury parameters as indicated in Annexure II(iv) of the Rules supra to evaluate this aspect.

64. The Designated Authority is required to examine whether the cessation of the existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The injury to the domestic industry is, therefore, required to be examined in the context of its continuation or recurrence. Further,

existence of anti dumping duty in force is required to be kept in view while examining the injury to the domestic industry.

65. The Authority has gone through the submissions made by the domestic Industry and the importer as mentioned above. The Authority notes that there have been no imports of subject goods from any of the subject countries during the POI. In view of this fact the Authority notes that there has been no volume injury to the domestic Industry during these periods.
66. M/s RIL, the domestic Industry has claimed that the domestic industry has been able to sustain the existing price level primarily on account of the existence of the Anti dumping duties. The domestic Industry has also claimed that their quantum of sales have increased though the sales have decreased in the value terms. They have also added that the expected fair price as worked out by them is Rs ****/MT during the POI for the subject goods and withdrawal of the Anti dumping duties would certainly result in price depression, suppression, and eventual loss or severe loss of reasonable profit which are more than sufficient to justify the continuation of Anti Dumping duties on the imports of PTA from the subject countries.
67. As regards the price injury, the Authority has examined the various injury parameters as per the Annexure II of the Rules of the Anti Dumping.

- (i) Volume of Imports and Market Share: It is claimed by the domestic industry that there has been no imports of the subject goods during the Period of Investigation from the subject countries. The Authority has examined the volume of imports from the subject countries as made available by the DGCI&S and concludes that there has been no import of the subject goods from the subject countries during the POI. From the information made available to the Authority, it is noted that the market share of the domestic industry has declined from 80% in 99-00 to 64% during the POI. The demand of the subject goods has not shown any significant change during POI and previous two years. For calculating the demand, the Authority has taken into account the sales of the domestic Industry, production of other producers as made available by the domestic Industry (None of the other producers has submitted any relevant data) and volume of imports into India.

Market Share			
	99-00	00-01	2001-02A)
Domestic Ind %	80.92	69.97	64.98
Others producers %	14.61	29.01	35.01
Imports %	4.47	1.01	0

(ii) Capacity Utilisation: The Authority notes that their capacity utilization has increased during the POI as compared to previous years. The Authority notes that capacity utilization of the subject goods continues to be high during the POI as also during the previous years.

(iii) Production: The production of the subject goods has shown a marginal improvement during the POI as compared to earlier periods. The Authority notes that the domestic industry has been able to achieve high production during the POI and previous years.

(iv) Sales Volumes: Sales have declined in terms of quantity and value during the POI as compared to previous years. They have declined by ****% in quantity and****% in value from 1999-00 to 2000-01. However, the sales volumes have shown an upward increase by ****% in term of quantity from 2000-01 to POI.

(v) Exports: The domestic industry has been able to achieve a significant export growth during the POI in terms of quantity as well as value over 99-00. In fact, the domestic industry has increased export sales of ****% in terms of quantity and ****% in terms of value over 99-00.

(vi) Opening Stock & Closing Stocks: The opening stock has considerably declined during the POI as compared to year 99-00 while the closing stock has remained largely the same.

(vii) Profit/Loss: The profitability of the domestic industry has declined during the POI as compared to the year 99-00.

68. The Authority has taken into account the aforesaid indices regarding injury and the existing anti-dumping duty on PTA imports, while doing the final determination so as to arrive at conclusions as to whether the withdrawal of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated base consumption norms and the actual price of the

raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation.

69. The Authority notes that the Net Sales Realisation of the subject goods has not been below the NIP during the POI so there has been no underselling of the subject goods by the domestic Industry.
70. The Authority further notes on the basis of the information provided by domestic Industry and other interested parties that domestic industry has not suffered any price undercutting and price suppression for the POI, as there has not been any imports of the subject goods from the subject countries. In view of the above, it can be concluded that the domestic industry has not suffered any material injury during the POI on account of imports from subject countries. The decline in the market share and profitability for the domestic industry may have happened on account of internal competition from the other domestic producer of the subject goods and therefore there does not appear to be enough evidence to suggest that cessation of anti dumping duty would cause recurrence of injury and dumping.
71. As per the section 9A(5) of the Anti-Dumping Rules, in the case of Sunset Review, the Central Government has to form an opinion that the cessation of anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. M/s. Reliance Industry has claimed that in the absence of antidumping duty on the subject goods, the domestic industry would be forced to reduce its price immediately to the extent ranging from Rs.1695 PMT to Rs.3375 PMT. It has also been claimed that withdrawal of anti dumping duty would result in the landed price of the subject goods becoming less than the net selling price of the domestic industry. This would result in price depression, price suppression and eventual loss of reasonable profit, which are more than sufficient to justify the continuation of the anti dumping duties on the imports of PTA from the subject countries.
72. The domestic Industry has also drawn the attention of the Authority towards the provisions of De minimus dumping margin and De minimus volumes indicating that these are not applicable to the Sunset review cases under Rule 23(3). Further they also aver that Rule 14 has not been made applicable in cases of Sunset Review under Rule 23(3). They have also drawn the attention of the Authority towards the judgment made by Hon'ble CEGAT in the case of IBB wherein the Order States that Designated Authority should record a finding that import of dumped articles into India causes or threatens material injury to any established industries in India. As a result of this provision, Designated Authority was bound to examine whether import of IBB from China PR will threaten material injury to

any established industry in India in case the anti-dumping duty, which was in force, is discontinued. It was further held by the CGEAT that as a consequence to the imposition of anti dumping duty on IBB imported from China, the domestic industry might not have suffered any injury during the present period of investigation. When the anti dumping duty is discontinued would any threat of material injury to Indian Industry recur.

- 73 The domestic industry has further drawn the attention of the Authority towards the WTO Panel Decision on the Issue of De-minimus or no imports in case of US-Drams from Korea. The Panel examined the text of Article 11.2 of the Anti-Dumping Agreement and rejected Korea's assertion that Article 11.2 requires immediate revocation of anti dumping duty as soon the importer is found to have ceased dumping and that the continuation of an anti-dumping duty is precluded a priori in any circumstances other than where there is present dumping. The Panel further noted that the Sunset provision of Article 11.3 envisages a determination of whether the expiration of an antidumping duty would lead to a continuation or recurrence of dumping.
- 74 The authority notes that none of the exporters has participated in this investigation except M/s. P.T. Polyprima, Indonesia. However, the cooperating exporter M/s. PT Polyprima, Indonesia had not exported any subject goods from Indonesia during the POI and previous years and nor they have participated in the earlier investigations. From the import statistics made available by DGCI&S Kolkata, the domestic industry and the importer, the authority notes that import of subject goods from countries other than the subject countries have declined from 63648 MT during 1999-00 to NIL MT during the POI. Even the imports from the subject countries have declined from 2021 MT during 1999-00 to nil during the POI. It has been claimed by the importer that even higher imports during the earlier periods have all been routed through advance license. The Authority finds it significant to note that imports from even countries other than subject countries have declined to NIL during the POI.
- 75 The Authority, therefore, does not find merit in the submission of domestic industry that their net selling price of the subject goods would get reduced to the extent of anti dumping duty which had earlier been imposed during the original as well in the review investigations, if the authority revokes the anti dumping duty in this present sunset review. The Authority notes that even in the absence of anti dumping duty from countries other than subject countries, no imports have been taken place with respect to subject goods. The Authority further notes that the decline in the imports from the countries other than subject countries has happened despite reduction in the customs duty. It is also noted by the

Authority that demand of the subject goods in India has not shown any significant change during the POI as compared to previous years. The Authority, therefore, notes that there is no basis for the domestic Industries claim that in the absence of Anti Dumping measures there will be a recurrence of imports from the subject countries and consequent injury to it. The Authority therefore cannot conclude reasonably that existence of Anti Dumping Duty has caused the imports to decline to zero from the subject countries when the imports from countries to which no Anti Dumping duty applies have similarly declined to zero.

- 76 In line with the observations made by the CEGAT, the Authority has further analyzed the fact that as a result of the withdrawal or discontinuation of anti dumping duty, would there be any threat to the domestic industry in terms of recurrence. The Authority notes that sub-rule VII to the Annexure II of the Anti-Dumping Rules states that a determination of the threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in the circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. The domestic industry has claimed that there exists a massive exportable surplus in the subject countries, which would clearly indicate that the same would find their way into India if the antidumping duties were removed. However, with regard to the other factors, no threat of injury had been claimed by the domestic industry. The Authority, therefore, concludes that evidence presented by the domestic industry does not demonstrate the likelihood of the recurrence of exports to India at dumped prices in the absence of Anti Dumping measures.
77. The above economic indicators imply that the cessation of anti dumping duty on the subject goods will not lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry and therefore the Authority recommends discontinuance of the anti dumping duty on the subject goods.
78. Landed Value: In the absence of any imports of subject goods from the subject countries during the POI the authority could not determine the landed value of the subject goods from the subject countries.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing that:

- (i) Pure Terephthalic Acid (PTA) originating in or exported from Indonesia, Thailand, and Korea (RP) has not been exported to India during the POI.
- (ii) The domestic industry has not suffered material injury from the import of subject goods from the subject countries.
- (iii) Various economic indicators and injury parameters imply that the cessation of anti dumping duty on the subject goods will not lead to continuance or recurrence of dumping and injury and therefore the Authority recommends discontinuance of anti dumping duty on Pure Terephthalic Acid (PTA) exported to India from Indonesia, Thailand and Korea (RP).
- (iv) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority and Addl. Secy.